● वर्ष-3
● अंक-71
रायपुर, बुधवार
01 नवंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› करवा चौथ और संकष्टी चतुर्थी ...

अब केन्द्र पर फोन में 'सेंधमारी' के आरोप

विपक्षी नेताओं ने दावा किया, सरकार ने जांच का आश्वासन दिया

नईदिल्ली। विपक्ष के कई नेताओं ने मंगलवार को दावा किया कि उन्हें उनके आईफोन में सरकार प्रायोजित सेंधमारी के प्रयास' के बारे में एप्पल से चेतावनी संदेश मिला है तथा इस कथित हैकिंग के प्रयास के लिए सरकार जिम्मेदार है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सरकार इसकी गहन जांच कराएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल, शशि थरूर, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत एवं टी एस सिंहदेव, शिवसेना (यूबीटी) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा, माकपा महासचिव सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम)के असदुद्दीन ओवैसी को भी इसी तरह का संदेश मिला है।

आईफोन निर्माता एप्पल ने मंगलवार को कहा कि वह विपक्षी दलों के कुछ सांसदों को भेजे गए चेतावनी संदेश को किसी विशिष्ट सरकार-प्रायोजित सेंधमारों से नहीं जोड़ती और वह इस बारे में जानकारी नहीं दे सकती है कि ऐसी चेतावनियों का कारण क्या है। कंपनी ने कहा, ''ऐसे हमलों का पता लगाना

खतरे के खुफिया संकेतों पर निर्भर करता है जो अक्सर अपूर्ण और अधूरे होते हैं। यह संभव है कि एप्पल के खतरे संबंधी कुछ सूचनाएं गलत चेतावनी हो सकती हैं या कुछ हमलों का पता नहीं चल पाता।'' हालांकि, एप्पल ने इस बारे में बताने से इनकार कर दिया कि विपक्षी नेताओं को किस वजह से चेतावनियां मिलीं। विपक्षी नेताओं को जवाब देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अमित मालवीय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हमेशा की तरह कुछ ही लोग सरकार प्रायोजित हमले पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं और खुद को शहीद बताने का नाटक कर रहे हैं... सब अच्छा है... लेकिन संभावना है कि हमेशा की तरह ही इस हंगामे की हवा निकल जाएगी!''उन्होंने कहा, एप्पल के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा क्यों न की जाए? या हंगामा खड़ा करने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहते ? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि उनकी पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के आईफोन को सरकार प्रायोजित हैकर्स द्वारा हैक करने का प्रयास किया गया और यह अडाणी समूह के मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश भर है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि उद्योगपति गौतम अडाणी देश में नंबर एक हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नंबर आता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब भी अडाणी से जुड़ा मामला उठाया जाता है तो एजेंसियों को जासूसी में लगा दिया जाता है। उन्होंने सरकार को चुनौती देते हुए कहा, ''जितनी टैपिंग करनी है कर लो, हम डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।''

महुआ मोइत्रा और प्रियंका चतुर्वेदी इस मुद्दे को उठाने वाली विपक्षी नेताओं में सबसे पहले रहीं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा 'एक्स' पर पोस्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को टैग किया और कहा, ''आपसे आग्रह है कि आप राजधर्म निभाएं और गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करें। विशेषाधिकार समिति को इस मामले पर विचार करना चाहिए। अश्विनी वैष्णव को इस असली सेंधमारी के बारे में चिंता करनी चाहिए।'' प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एक स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि यह उन्हें एप्पल से प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। गृह मंत्री कार्यालय के ध्यानार्थ।'' तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी इसी तरह का पोस्ट किया। उन्होंने एक्स पर तंज कसते हुए कहा, ''एप्पल आईडी से प्राप्त हुआ, जिसका मैंने सत्यापन किया है। प्रामाणिकता की पुष्टि हुई। मेरे जैसे करदाताओं के पैसे पर अल्प-रोज़गार अधिकारियों को व्यस्त देखकर खुशी हुई!''

थरूर ने अपने पोस्ट के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को भी टैग किया। इसी तरह का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए खेड़ा ने कहा, ''प्रिय मोदी सरकार, आप यह क्यों कर रही हो?'' आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने एक लंबे पोस्ट में कहा कि उन्हें एप्पल से संबंधित अधिसूचना मिली है, जिसमें उनके फोन पर संभावित सरकार-प्रायोजित स्पाइवेयर हमले के बारे में चेतावनी दी गई है। चड्ढा ने कहा कि जासूसी आम चुनाव से महज कुछ महीने पहले हो रही है और इसे विपक्ष पर व्यापक हमलों के अंतर्गत रखा जाना चाहिए।

उज्ज्वला योजना - दो मुफ्त रसोई गैस सिलेण्डर मिलेगा

नईदिल्ली। प्रवक्ता के मुताबिक मंत्रिमण्डल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को नया आयाम देने के प्रयास के तहत प्रदेश की उचित दर की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन सहित ई-पॉस मशीनों की स्थापना और संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्रदेश के उचित दर की सभी 79 हजार दुकानों में ई—कांटे से लिंक उन्नत ई-पॉस मशीनों की स्थापना एवं संचालन के लिये 'सिस्टम इन्टीग्रेटर' संस्थाओं का चयन खुली निविदा के जरिये किया गया है। नयी ई-पॉस मशीनें 4-जी सिम से चलेंगी। ये मशीनें 'फिंगरप्रिन्ट एवं आईरिस स्कैनर' से लैस हैं। इन मशीनों से उचित दर विक्रेताओं को उनकी आमदनी बढ़ाने वाली अन्य कम्प्यूटरीकृत सेवाएं भी उपलब्ध करायी जा सकेंगी।

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो मुफ्त रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल दिये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दो नि:शुल्क रसोई गैस सिलेण्डर रिफिल देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत अक्टूबर-दिसम्बर 2023 तथा जनवरी-मार्च 2024 में लाभार्थियों को मुफ्त सिलेण्डर रिफिल वितरित किये जाएंगे। इस योजना पर राज्य सरकार हर साल 2312 करोड़

रुपये खर्च करेगी। राज्य में 1.75 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जाएगा। इनमें से प्रथम चरण में आधार प्रमाणित लाभार्थियों को नि:शुल्क सिलेण्डर रिफिल का वितरण किया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने एक अन्य अहम फैसले में मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमण्डल ने जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिये मिर्जापुर में संस्कृति विभाग की 4.046 हेक्टेयर जमीन, सोनभद्र में 2.828 हेक्टेयर भूमि तथा महराजगंज में 0.506 हेक्टेयर भूमि को समाज कल्याण विभाग के अधीन संचालित 'अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ ' के पक्ष में आवंटित किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं, जो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहती हैं। इनमें भौगोलिक असमानता के साथ-साथ रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, कला इत्यादि क्षेत्रों में पर्याप्त विविधता पायी जाती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता आज भी सभी का मार्गदर्शन करती है।

जौहर ट्रस्ट को दी गई जमीन वापस ली जाएगी

मंत्रिमण्डल ने लिया फैसला

नईदिल्ली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां के संरक्षण वाले मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को फरवरी, 2007 में पट्टे पर दी गई करोड़ों रुपये की 41 हजार वर्ग फुट से ज्यादा जमीन को शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में वापस लेने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी। राज्य सरकार का यह फैसला जाली जन्म प्रमाणपत्र मामले में इस वक्त जेल में बंद आजम खां के लिए एक और बड़ा झटका है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए कहा, रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को पट्टे पर दी गई 41,181 वर्ग फुट जमीन जिन शर्तों के आधार पर आवंटित की गई थी, उनका उल्लंघन किया गया।खास तौर से यह जमीन विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए दी गई थी लेकिन उस पर एक राजनीतिक दल (सपा) का कार्यालय बना दिया गया, इसलिए मंत्रिमण्डल ने वह भूमि अब वापस लिए जाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, वर्ष 2007 में यह भूमि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट

को 100 रुपये वार्षिक की दर से 30 वर्ष के लिए पट्टे पर दी गई थी। अब मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक स्कूल का भवन और जमीन वापस लेते हुए इसका स्वामित्व माध्यमिक शिक्षा विभाग को देने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने मंजूर कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, वर्ष 2007 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री आजम खां ने रामपुर के तोपखाना मार्ग स्थित पुराने मुर्तजा स्कूल भवन और जमीन को जौहर ट्रस्ट के नाम 100 रुपये प्रतिवर्ष की दर पर 30 वर्षों के लिए आवंटित करा लिया था।

आरोप है कि इस जमीन को मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए पट्टे पर दिया गया था, लेकिन इस पर आजम खां का कार्यालय दारूल अवाम बनाया गया, जहां से सपा की स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता था। इसके अलावा इसी जमीन के एक हिस्से में रामपुर पब्लिक स्कूल स्थापित किया गया। मंत्रिमण्डल के इस फैसले के बाद दोनों भवनों को खाली कराया जाएगा। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने जमीन आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की थी। सक्सेना ने पीटीआई- को बताया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के पट्टा विलेख के बिंदु संख्या-7 में साफ तौर पर लिखा है कि आवंटित जमीन पर एक वर्ष के अंदर विश्वविद्यालय के संचालन के लिए निर्माण कराया जाएगा।

इसके अलावा किसी अन्य काम के लिए उस भूमि का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

प्रमुख समाचार

कांग्रेस का विकास से लेना-देना नहीं: शिवराज सिंह

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अब प्रचार तेज होता दिखाई दे रहा है। रतलाम मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने

कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बदल गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस का विकास से कोई लेना-देना नहीं है। कांग्रेस के नेताओं का मध्य प्रदेश से भावनात्मक रिश्ता नहीं है। खुद मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। हमारा संकल्प है कि हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि सवा साल के लिए कांग्रेस की सरकार आयी थी। तब कमलनाथ ने प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया था।एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो मेरा श्राद्ध तक कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते, ये कन्यापूजन को नाटक-नौटंकी बताते हैं और महिलाओं के लिए अपशब्दों का उपयोग करते हैं। शिवराज ने दावा किया कि मध्यप्रदेश अब बदल गया है। आज विकास के मामले में मध्यप्रदेश हिंदुस्तान के नम्बर-1 के राज्यों की पंक्ति में खड़ा हो गया।

मेरी माटी-मेरा देश: अमृत कलश यात्रा का समापन समारोह

नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश-अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने एक डिजिटल प्रदर्शनी देखी। उन्होंने युवाओं के लिए मेरा युवा

भारत (एमवाई भारत) मंच की शुरुआत की और अमृत महोत्सव स्मारक एवं अमृत वाटिका का वर्चुअली शिलान्यास किया। उन्होंने अमृत महोत्सव के दौरान हासिल की गई सफलताओं- चंद्र मिशन, वंदे भारत ट्रेन, देश के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बारे में बात की। पीएम मोदी ने कहा कि आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कर्तव्य पथ एक ऐतिहासिक महायज्ञ का साक्षी बन रहा है। 12 मार्च 2021 को गांधी जी की प्रेरणा से साबरमती आश्रम से शुरू हुआ आजादी का अमृत महोत्सव अब 31 अक्तूबर 2023 आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर समापन का पल है। आज ये हुजूम एक नया इतिहास बन गया। जैसे दांडी यात्रा शुरू होने के बाद देशवासी उससे जुड़ते गए, वैसे ही आजादी के अमृत महोत्सव ने जनभागीदारी का ऐसा हुजूम देखा कि नया इतिहास बन गया। 75 साल की ये यात्रा समृद्ध भारत के सपने को साकार करने वाला कालखंड बन रहा है।

केरल: शत्रुता बढ़ाने के आरोप में भाजपा नेता पर मामला दर्ज

नईदिल्ली। केरल पुलिस ने बुर्का पहनी महिला के बारे में सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट साझा कर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप में मंगलवार को भारतीय

जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अनिल के. एंटनी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया। कासरगोड जिला साइबर प्रकोष्ठ ने कहा कि 'एक्स' पर एंटनी का पोस्ट विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के समान है, जिसके चलते भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 153ए धर्म, नस्ल, जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के गैर-जमानती अपराध से संबद्ध है।एंटनी के खिलाफ प्राथमिकी, 'एक्स' पर एक विवादास्पद पोस्ट के सिलसिले में शुरूआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई थी। साइबर प्रकोष्ठ ने खुद से 27 अक्टूबर को यह प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में, एंटनी ने पोस्ट को साझा किया और उसपर टिप्पणी करते हुए कहा, ''उत्तरी केरल में बुर्का पहने बिना बस में यात्रा नहीं।'' पुलिस ने बताया कि मंगलवार को, उनका नाम प्राथमिकी में आरोपी के तौर पर जोड़ा गया।

महाराष्ट्र में मराठों को मिलेगा कुनबी जाति का प्रमाणपत्र

मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि वह कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग पर कार्रवाई शुरू करेगी, जो उन्हें ओबीसी श्रेणी में

आरक्षण के लिए पात्र बनाती है। सरकार ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली समिति की पहली रिपोर्ट स्वीकार कर ली। मराठवाड़ा क्षेत्र में विशेष रूप से मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए समिति की स्थापना की गई थी। सीएम एकनाथ शिंदेन ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए समाधान खोजने के लिए मंगलवार को एक तत्काल कैबिनेट बैठक की। जस्टिस शिंदे ने मराठवाड़ा के निज़ाम काल के दौरान मराठा कुनबी और कुनबी मराठा के दस्तावेजों की जांच की थी। पिछड़ा वर्ग आयोग अब मराठा समुदाय के शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन की जांच करेगा। वहीं, न्यायमूर्ति दिलीप भोसले की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति मारोती गायकवाड़ और न्यायमूर्ति संदीप शिंदे की समिति मराठा आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार को कानूनी सलाह देगी।

जम्मू-कश्मीर: आतंकियों ने लगातार तीसरे दिन किया हमला

बारामुला। कश्मीर घाटी में दहशतगर्दों ने एक बार फिर आतंकी हमले को अंजाम दिया है। ये लगातार तीसरा दिन है जब हमला हुआ है। आज बारामूला में जम्मू-कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को उनके घर के पास गोली मारी गई। वारदात को अंजाम देकर आतंकी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल पुलिसकर्मी को लोगों ने अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया है। हालांकि कि डॉक्टर उनकी जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। इससे पहले आतंकी बीते 48 घंटे में भी दो वारदातों को अंजाम देकर घाटी में दहशत फैला चुके हैं। पहले पुलवामा में 29 अक्तूबर को यूपी के मजदूर को गोली मारी गई फिर श्रीनगर में 30 अक्तूबर को क्रिकेट खेल रहे पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी को गोली मारकर घायल कर दिया।आतंकियों की बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर कश्मीर के सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया है। विशेष नाके लगाकर वाहनों तथा पैदल आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। पुलिस के अनुसार हमले में लश्कर-ए-ताइबा के दो आतंकी शामिल रहे हैं। इनमें से एक पुलवामा का रईस डार है। घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की। इसके बाद पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया ताकि हमले में शामिल आतंकियों को खोज निकाला जाए।

मुफ्त की रेवड़ियों के वादे, जनता को लुभाने के इरादे

समीर चौगांवकर

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के समय मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राजनीतिक दलों की फ्रीबीज योजनाओं पर तंज कसते हुए कहा था कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में क्या फ्री में देगी यह कहने का अधिकार उन्हें है, लेकिन इसके साथ ही वोटरों को यह जानने का भी अधिकार है कि किसी घोषणा को कब, कैसे और कितना लागू करेंगे?

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक प्रोफार्मा (प्रारूप) राजनीति दलों के लिए जारी किया है, जिसमें राजनीतिक पार्टियों को बताना होगा कि उनकी कोई भी मुफ्त वाली घोषणा के लिए डेब्ट टू जीडीपी रेश्यो क्या होगा? आप कितना लोन लोगे? कुल राजस्व प्राप्ति से ब्याज कितना अदा होगा? चुनाव आयोग ने यह भी पूछा कि फिस्कल रिस्पांन्सिब्लिटी एंड बजट मैनेजमेंट (एफआरबीएम) के टारगेट तोड़ोगे या नहीं? क्या किसी योजना को बंद कर नई योजनाएं लागू करेंगे या लोगों पर अतिरिक्त कर लगाएंगे?

प्रधानमंत्री मोदी लगातार राज्य सरकारों की फ्रीबीज घोषणाओं को %रेवडी% संस्कृति% बताकर या राजकोषीय फिजूलखर्ची कहकर निंदा करते रहे हैं। वो मतदाताओं को इससे दूर रहने की नसीहत भी देते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि केन्द्र की मोदी सरकार ने भी रेवड़ियां बांटने में कोई कमी नहीं रखी है। मोदी सरकार भी

अपनी वेलफेयर स्कीम के दम पर लाभार्थियों को एक वोटबैंक के रूप में टार्गेट करती है। सभी राज्य सरकारें विधानसभा चुनाव जीतने के लिए तमाम फ्रीबीज योजनाओं को आगे कर %लाभार्थी% का एक बड़ा वोट बैंक तैयार करने में जुटी हैं जिससे चुनाव में उसकी फसल काटी जा सके।

मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सरकार की 10 बड़ी योजनाओं पर ही 23 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी। खासकर लाड़ली बहना योजना, जिस पर 1 करोड़ 31 लाख लाभार्थियों को प्रतिमाह 1250 रूपये देने के हिसाब से सालाना 19 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे। शिवराज सरकार का वादा है कि सत्ता में आने पर इसे 3000 रूपये तक कर देंगे। कमलनाथ ने भी सत्ता में आने पर नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रूपये हर महिला के खाते में डालने का वादा किया है। अभी कांग्रेस और भाजपा का घोषणा पत्र नहीं आया है। ऐसे में तय है कि दोनों दलों के घोषणा पत्र में रेवड़ी जमकर बंटेगी। शिवराज सरकार ने 3 साल में कुल 2715 घोषणाएं की है। इसमें से 592 घोषणाएं चुनावी साल में हुई है।

चुनाव से छह महीने पहले शिवराज सरकार ने 4 बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी। इसमें लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत 1 करोड 31 लाख महिलाओं के खाते में 1250 रूपये डाले जायेंगे। कुल खर्चा 19650 करोड़ रूपये। किसान सम्मान निधि योजना जिसमें प्रदेश के 87 लाख किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 4 हजार से बढ़ाकर 6 हजार करने की घोषणा। कुल खर्चा 1750 करोड़ का। मेधावी छात्रों को लैपटॉप बांटना जिसके अंतर्गत 12 वीं कक्षा के 78,641 मेधावी छात्रों के खाते में 25 हजार रूपये डालना। कुल खर्च 196 करोड़ रूपये। इसके अलावा प्रदेश के 7,800 छात्रों को स्कूटी बांटने के लिए 90 हजार करोड़ रूपये का बजट देना भी शामिल है।राजस्थान में भी अशोक गहलोत सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए फ्रीबीज को अपना सबसे प्रमुख हथियार बनाया है। गहलोत ने राजस्थान में ईडी के प्रवेश के साथ ही सात गारंटियों की घोषणा की है। इन सात गारंटी को देखें तो, पहली गारंटी है गृह लक्ष्मी गारंटी, जिसमें परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10 हजार रुपए मिलेंगे। दूसरी गारंटी है गौ-धन गारंटी। इसमें 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा।

तीसरी गारंटी है फ्री लैपटॉप-टैबलेट गारंटी, इसमें सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे विद्यार्थियों को पहले वर्ष में लैपटॉप या टैबलेट मुफ्त दिए जाएंगे। चौथी गारंटी है चिरंजीवी आपदा राहत गारंटी बीमा, इसमें प्राकृतिक आपदा आने पर 15 लाख रुपए तक का फ्री बीमा है। पांचवीं गारंटी है, अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा फ्री गारंटी। इसमें हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी है।

छत्तीसगढ़ में आज से होगी धान की खरीदी

158529 किसानों ने धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया, इस साल 5529 किसानों की संख्या बड़ी

बेमेतरा। पूरे छत्तीसगढ़ सहित बेमेतरा जिले में कल 1 नवम्बर से जिले के 129 धान उपार्जन केंद्र किसानों से गुलज़ार होंगे। किसानों को उनकी मेहनत का लाभ मिलने की शुरुआत होगी, यानी धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। इसी को लेकर कलेक्टर श्री पदुम सिंह एल्मा ने आज यहां जिला पंचायत के सभाकक्ष में उपार्जन स्तरीय नोडल अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने मानसिक व शारीरिक रूप से धान खरीदी के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए। सभी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त करने कहा । किसानों को कोई परेशानी, असुविधा ना हो इसका ख्याल रखने कहा। उपार्जन केंद्रों में छाया-पानी की व्यवस्था करने कहा। कलेक्टर ने अधिकारियों से सुगम धान खरीदी के लिए सतर्क रहकर सौपे गये दायित्वों का पालन करने की बात कही। ताकि किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो। उन्होंने आदर्श आचरण संहिता का पालन करने के निर्देश दिए बैठक में उप संचालक कृषि श्री मोरध्वज डड़सेना, ज़िला खाद्य अधिकारी नीतीश त्रिवेदी सहित उपार्जन नोडल अधिकारी उपस्थित थे।

धान एवं मक्का का उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ एवं छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान की खरीदी विगत खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में संचालित और नवीन बनाए गए खरीदी केन्द्रों में की जाएगी। इस प्रकार जिले की 102 सहकारी समितियों के सभी 129 खरीदी केंद्रों में धान किया जाएगा।

जिले में खरीफ सीजन 2023-24 में जिले में अब तक 158529 किसानों ने धान विक्रय हेतु सहकारी समितियों में पंजीयन कराया हैं। पिछले साल 1 लाख 53 हज़ार किसानों ने धान विक्रय हेतु सहकारी समितियों में पंजीयन कराया था। जिनका रकबा 1 लाख 83 हज़ार 242 हेक्टेयर था। जो बड़ कर इस साल 1 लाख 85 हज़ार 928 हेक्टेयर हो गया है। जो किसान अभी तक पंजीयन नहीं कराए है वह आज 31 अक्टूबर तक करा सकते है। इस साल धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य 802842 मैट्रिक टन है। पिछले साल अनुमानित लक्ष्य 679187 मैट्रिक टन था।

भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 2023-24 के लिए औसत अच्छे किस्म के कॉमन धान के लिए 2183 रूपए और ए-ग्रेड धान के लिए 2203 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय किया गया है। मक्के के लिए 2090 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य होगा।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवम्बर से 31 जनवरी 2024 तक और मक्का की खरीदी 1 नवम्बर से 28 फरवरी 2024 तक की जाएगी। राज्य सरकार के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय से जारी दिशा-निर्देशानुसार धान खरीफ वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों से धान खरीदी की अधिकतम सीमा 20 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। इसी प्रकार मक्का खरीदी की अधिकतम सीमा 10 क्विंटल प्रति एकड़ लिंकिंग सहित निर्धारित की गई है। इस बार धान खरीदी कार्य में पारदर्शिता के लिए बायोमेट्रिक आधारित खाद्यान्न उपार्जन प्रक्रिया से किया जायेगा। धान और मक्का खरीदी की समस्त राशि का भुगतान किसानों के खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा।

भाजपा और कांग्रेस से आप प्रत्याशी के पांच सवाल, जवाब देने पर नहीं लड़ेंगे चुनाव

जगदलपुर। 7 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मतदान को लेकर प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार प्रसार धुंआधार तरीके से चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार में जुटे हैं। बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों पर एक मात्र जगदलपुर विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित है। इस सीट को काफी हाई प्रोफाइल माना जाता है। सभी पार्टी चाहती हैं कि उनका कब्जा इस सीट पर हो। इस सीट पर केवल बीजेपी और कांग्रेस छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद काबिज रहे हैं। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था। लेकिन इस बार शायद मुकाबला त्रिकोणीय हो।

छत्तीसगढ़ विधानसभा 2023 के चुनाव में जगदलपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने चुनौती पेश की है। ऐसा लग रहा है कि अबकी बार चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देगी। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा के हर क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच मीडिया ने जनसंपर्क के दौरान जगदलपुर विधानसभा के आम आदमी पार्टी प्रत्याशी नरेंद्र भवानी से बातचीत की। जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की दोनों ही बड़ी पार्टियों से कुछ सवाल पूछे हैं।

आप प्रत्याशी नरेंद्र भवानी ने कहा दोनों ही पार्टियों की सरकार छत्तीसगढ़ में रही है। लेकिन इन सभी मूलभूत सुविधाएं का हाल बद से बदतर है। इनकी व्यवस्था अभी तक दोनों ही सरकार ने नहीं की है। 22 साल तक ये पूरा नहीं हुआ। अबकी बार फिर 2023 में फिर से दोनों पुरानी चीजों को ठीक करने की बात कह रहे हैं। इन सवालों का जवाब अगर बीजेपी कांग्रेस देती है तो वो जगदलपुर विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ेंगे।

इसके नरेंद्र भवानी ने रुपये पैसे देकर अरविंद केजरीवाल की सभा में भीड़ जुटाने की बात का खंडन किया है। नरेंद्र भवानी के मुताबिक यदि पैसे देकर भीड़ बुलाई गई होती तो विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार तगड़ा होता। पूरे शहर से लेकर गांव तक बड़े-बड़े बैनर पोस्टर लगे होते। लेकिन आम जनता की यह लड़ाई है। हार जीत की नहीं है। नरेंद्र भवानी के मुताबिक वो जगदलपुर विधानसभा से चुनाव जीत रहे हैं,पूरे प्रदेश के साथ बस्तर में आम आदमी पार्टी की 10 गारंटी काम करेगी।

बिलासपुर में नामांकन के बाद अमर अग्रवाल पर बरसे शैलेष पांडेय

■ **बिल्हा से सियाराम कौशिक ने भाजपा पर लगाए बड़े आरोप**

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन सभी 70 सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। बिलासपुर में भी सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा। कांग्रेस प्रत्याशी शैलेष पांडेय ने नसबंदी कांड को याद किया तो बिल्हा से कांग्रेस प्रत्याशी सियाराम कौशिक ने भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।

बिलासपुर प्रत्याशी शैलेष पांडेय ने पूर्व मंत्री व भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल और उनके पहले के कार्यकाल में हुए मामलों को लेकर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में सीवरेज योजना के कारण शहर को 20 साल में खोदापुर बना दिया। नसबंदी कांड को एक बार फिर याद कर शैलेष पांडेय ने अमर अग्रवाल को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि अमर अग्रवाल के कार्यकाल में नसबंदी कांड में 13 महिलाओं की मौत का जिम्मेदार अमर अग्रवाल है। इसे बिलासपुर की जनता के साथ ही पूरे देश ने देखा है। ऐसे लज्जाहीन नेता को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है।

बिल्हा विधानसभा प्रत्याशी सियाराम कौशिक ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। उनके विधान सभा क्षेत्र के भाजपा से प्रत्याशी धरमलाल कौशिक के चुनाव लड़ने पर कौशिक वर्सेस कौशिक पर सियाराम ने भूपेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद किसानों के लिए कर्जमाफी, राजीव गांधी न्याय योजना, 20 क्विंटल धान खरीदी जैसे बड़े बड़े काम किए गए हैं निश्चित ही इसका फल मिलेगा। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में भाजपा को हराकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बिलासपुर में चुनाव को देखते हुए पुलिस ने आदतन अपराधियों और आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की। अक्टूबर के महीने में कुल 1402 अपराधियों पर कार्रवाई की गई है। जबकि पिछले 10 महीने में 19544 लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। है 2022 में पूरे साल में कुल 3803 लोगो और 2021 में 1,858 लोगो पर एक्शन लिया गया था।

बेमेतरा विधानसभा से 21 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, साजा से ईश्वर साहू ने भरा पर्चा

बेमेतरा। बेमेतरा जिला के तीनों विधानसभा क्षेत्र साजा, बेमेतरा व नवागढ़ के लिए 56 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। जिसमें सबसे ज्यादा बेमेतरा विधानसभा से 21 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया। नवागढ़ विधानसभा से 19 व साजा विधानसभा से 16 प्रत्यशियों फॉर्म जमा किए। नाम वापसी की आखिरी तारीख 2 नवम्बर रखी गयी है।

विधानसभा क्षेत्र 68 साजा से ईश्वर साहू (भाजपा) डोनमनदास धृतलहरे (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़) रविन्द्र चौबे (इंडियन नेशनल कांग्रेस) वीर वर्मा (आम आदमी पार्टी) चन्द्र कुमार गेन्ड्रे, (सर्वधर्म पार्टी) राजेन्द्र पटेल, (जोहार छत्तीसगढ़) कुमार गायकवाड़ (गण सुरक्षा पार्टी) लक्ष्मी नारायण साहू, (भारतीय शक्ति चेतना पार्टी) अशोक जैन, ओम प्रकाश चतुर्वेदी, दीपक कुमार रात्रे, निखिलेश साहू, मंशाराम, सतीश सिंह राजपूत, सुनील कुमार, संजीव अग्रवाल ने नामांकन पत्र जमा किये।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 69 बेमेतरा से 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किये। उनमे आशीष छाबड़ा, (इंडियन नेशनल कांग्रेस) दीपेश कुमार साहू (भाजपा) संजीव अग्रवाल, अर्जुन सिंह ठाकुर, रूखमणी निषाद (जोहार छत्तीसगढ़) जितेन्द्र नौरंगें, गोपाल कुर्र प्रमोद कुमार साहू (आम आदमी पार्टी) चंद्रभान साह (भारतीय शक्ति चेतना पार्टी) उमाशंकर यादव (गोडवाना गणतंत्र पार्टी) दरवन सिंह वर्मा, बहलसिंह वर्मा, (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़) मनमोहन ठाकुर, बिरेन्द्र कुमार बंजारे (अंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया) गिरधारी देवांगन(समाजवादी पार्टी) तिलबाई साहू(राष्ट्वादी भारत पार्टी) प्रशून शुक्ला, (आज़ाद जानता पार्टी) भूनेश्वर गन, (सर्व धर्म पार्टी) सुखदेव टंडन, (राष्ट्रीय जनसभा पार्टी) रोहित सिन्हा, सुशील कोसले ने नामांकन पत्र जमा किये।

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 70 नवागढ़ से 19 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किये। उनमें दयालदास बघेल (भाजपा) गुरू रूद्र कुमार (इंडियन नेशनल कांग्रेस) भारती गंधर्व (राष्ट्रीवादी भारती पार्टी) गणिशंकर दिवाकर (भक्ति सेना) सनत कुमार (सर्वधर्म पार्टी) ओमप्रकाश वाजपेयी (बहुजन समाज पार्टी) जितेन्द्र कुमार लहरे (जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी) भानुप्रताप चतुर्वेदी कांशीराम बांधेए, राजेश धृतलहरे, भरत लाल पाटले (समाजवाद पाटी) शेष नारायण कुर्रे (जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़) नैनदास गायकवाड़, बुधारूराम, अंजोरदास धृतलहरे, दीपचन्द जोशी, अविनाश धृतलहर, ईश्वर दास, विनायक पनिक ने नामाकन पत्र जमा किये।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कोरबा में चुनाव के दौरान 9 हजार साड़ियों से भरा ट्रक जब्त

कोरबा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस का एक्शन जारी है। इसी बीच कोरबा में पुलिस ने साड़ियों से भरा एक ट्रक जब्त किया है। इस ट्रक में लगभग 23 लाख रुपये का सामान बताया जा रहा है। जब्त ट्रक के बारे में पुलिस जानकारी जुटाई जा रही है। आखिर यह साड़ी किसने मंगवाई थी और इसका मालिक कौन है। कोरबा जिले की उरगा पुलिस ने बीती रात जांच के दौरान एक ट्रक को रोक का और जब पीछे जाकर देखा तो पाया की ट्रक पूरी साड़ी से भरी हुआ है। ट्रक क्रमांक सीजी 04 एम 1895 को रोक कर जब उसकी जांच की गई तो ट्रक में 9000 साड़ी भरी मिली। ट्रक चालक द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दे पाने और आवश्यक कागजात न दिखा पाने की वजह से साड़ियों को जब्त कर लिया गया हैं। पुलिस को संदेह है कि यह साड़ियां चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभित करने के लिए बांटे जाने के उद्देश्य से मंगाई गई थी। बहरहाल, पुलिस ने धारा 102 के तहत गाड़ी और साड़ी दोनों को जब्त कर लिया है।

बस्तर विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को बस्तर संभाग में चुनाव है। चुनाव को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में हैं। लगातार चैकिंग कर अवैध कैश, शराब और अन्य सामान जब्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस ने दो सटोरियों को गिरफ्तार किया। जिनके कब्जे से भारी रकम बरामद की। बस्तर पुलिस ने चुनाव के बीच अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर जगदलपुर शहर में बड़ी कार्रवाई की। शहर के संजय इतवारी बाजार में ऑनलाइन व्हाट्सएप मैसेज के जरिए ऑनलाइन अंकों पर हार जीत का दांव लगाकर सट्टा खिलाया जा रहा था। इस सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पूरे जगह की घेराबंदी की गई। मौके पर दो सटोरियों को गिरफ्तार किया। जगदलपुर सीएसपी विकास कुमार ने बताया कि सटोरियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दंतेश्वर राव उर्फ दंती व रितेश कुमार त्रिवेदी हैं।

दूसरे चरण के नामांकन के बाद हाई अलर्ट पर पुलिस

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के 70 सीटों पर मतदान के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। जिसे देखते हुए सूरजपुर पुलिस हाई अलर्ट मोड में आ गई हैं। पुलिस ने अपनी सर्चिंग बढ़ा दी है। जिले से लगने वाले बॉर्डर और शहरों की इंट्री प्वाइंट पर चेकिंग बढ़ा दी गई हैं। हर जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध लोगों और सामान पर खास नजर पुलिस रख रही हैं। सूरजपुर एडिशनल एसपी शोभराज अग्रवाल ने बताया कि जिले के इंटरस्टेट बॉर्डर पर विशेष चेकिंग की जा रही है। रटोरी, अजबनगर, तारानगर, नवा टोला सहित 12 जगहों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। दिन रात चेकिंग की जा रही हैं। अवैध शराब, गांजा या कैश की चेकिंग कर जब्त किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन कार्य पूरा हुआ। 17 नवंबर को 70 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए 1219 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे। सूरजपुर जिले की तीन विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा।

कलेक्टर ने शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ

बेमेतरा। देश एवं प्रदेश के साथ ही जिले में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज 31 अक्टूबर मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। जिले के शासकीय अर्द्धशासकीय कार्यालयों व संस्थाओं में एकता दिवस की शपथ दिलाई गई। कलेक्टर कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामूहिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कलेक्टर श्री पदुम सिंह एल्मा ने कलेक्टोरेट स्थित विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी - कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। कलेक्टर द्वारा दिलाई गई शपथ को अधिकारियों और कर्मचारियों ने दोहराया। इस मौके पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज़िला पंचायत श्रीमती लीना कमलेश मंडावी, अपर कलेक्टर द्वय डॉ अनिल बाजपेयी, श्री सी एल मार्कण्डेय, एसडीएम एवं रिटर्निंग ऑफिसर साजा श्री विश्वास राव मस्के, उप ज़िला निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बंदे आदि उपस्थित थे।

सिरगिट्टी-तारबाहर फाटक दो दिन के लिये रहेगा बंद

बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर रेल मंडल के अन्तर्गत बिलासपुर एवं उसलापुर रेलवे स्टेशनों के बीच (सिरगिट्टी-तारबाहर फाटक) रेलवे फाटक क्रमांक 366 में बिलासपुर-उसलापुर फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई लाइन को बिलासपुर यार्ड से जोडने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के चलते 1 नवम्बर को रात्रि 11 बजे से 2 नवम्बर को सुबह 4 बजे तक रेलवे फाटक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। रेलवे फाटक बंद रहने के दौरान सड़क वाहन एवं स्थानीय नागरिकों का आवागमन बिलासपुर यार्ड के पूर्व में स्थित चुहचुहियापारा रोड अंडर ब्रिज एवं हेमूनगर रोड ओवर ब्रिज का उपयोग किया जा सकता है।

मनीष त्रिपाठी पर लगा फर्जी नामांकन पत्र दाखिल करने का आरोप

■ **अब अमित जोगी से मांगा जवाब**

मुंगेली। मुंगेली जिले के लोरमी विधानसभा में चुनाव रोचक मोड़ पर आ गया है। मनीष त्रिपाठी ने अभी तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) धर्मजीत सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद पार्टी का झंडा उठाये रखा था। पर अब कांग्रेस छोड़कर जेसीसीजे में आये सागर सिंह बैस को उम्मीदवार बना दिया।

मनीष त्रिपाठी को दरकिनार कर देने से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां पर जेसीसीजे की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को शिकायत की गई है कि किसी मनीष त्रिपाठी द्वारा जेसीसीजे से अपना नाम निर्देशन फार्म जमा किया गया है, वो फर्जी है। शिकायत में कहा गया है कि मनीष त्रिपाठी द्वारा नाम निर्देशन में जमा किए गए फार्म ए और फार्म बी में पार्टी के अध्यक्ष अमित जोगी और पार्टी के महासचिव महेश देवांगन के फर्जी हस्ताक्षर और पार्टी की फर्जी सील का इस्तेमाल किया गया है।

खुद को पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बताया गया है। शिकायत में जालसाजी और कूटरचना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस पूरे मामले पर जब जेसीसीजे के लोरमी विधानसभा प्रभारी मनीष त्रिपाठी से बात की गई तो वो पूरे मामले पर पार्टी प्रमुख अमित जोगी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं।

मनीष त्रिपाठी का कहना है कि अमित जोगी ने स्वयं लोरमी में आकर मुझे सब कार्यकर्ताओं के सामने बी फार्म दिया था। जिसकी फोटो भी मेरे पास है। मनीष त्रिपाठी ने कहा कि अब अमित जोगी को ये बताना होगा कि उनका दस्तखत फर्जी है या असली है। मनीष त्रिपाठी ने कहा कि जिस दिन अजीत जोगी ने पार्टी का गठन किया था। उस दिन से वो पार्टी के सदस्य हैं। मनीष ने कहा कि मेरे नामांकन रैली में पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष तिलक राम देवांगन खुद मौजूद थे। ऐसे में मेरा फार्म कैसे फर्जी हो सकता है।

6 नवंबर को मतदान दलों की शुरू हो जाएगी रवानगी

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में 7 नवंबर को मतगणना होनी है जिसके लिए निर्वाचन विभाग पूरी तैयारी में जुट गया है और विधानसभावार मतदान सामग्री वितरण के लिए केन्द्र भी बना दिए गए है। मतदान दलों को सामग्री के साथ 6 नवंबर को रवाना किया जाएगा जहां 7 नवंबर को मतगणना होगी। राजनांदगांव निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 74-डोंगरगढ़ (अनुसूचित जाति) अंतर्गत मतदान केन्द्रों की संख्या 173 है, जिसके लिए स्वामी आत्मानंद हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय डोंगरगढ़ को मतदान सामग्री वितरण केन्द्र बनाया गया है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 75-राजनांदगांव अंतर्गत मतदान केन्द्रों की संख्या 223 है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन बसंतपुर राजनांदगांव में मतदान दलों को मतदान सामग्री वितरण किया जाएगा।

चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज द्वारा जनजागरण कार्यक्रम

दुर्ग। वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के तारतम्य में छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालय चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के सामुदायिक चिकित्सा विभाग द्वारा आयोजित इस जनजागरण कार्यक्रम में चिकित्सा छात्र छात्राओं , इंटर्न व नर्सिंग छात्राओं को विशेष जानकारी दी गई। इस अवसर पर छात्रों के लिए एक पोस्टर प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा ग्राम कुरुद शासकीय उच्चत्तर विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इस शिविर में लोगों को आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों और उनके लक्षणों से परिचय कराया गया। इसमें घैंगा (गोवाइटर) नामक बीमारी से बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई और उसका उपचार के उपाय बताये गए। इस उपलक्ष में ग्राम कुरुद में इस बीमारी की रोकथाम के प्रति जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर व पोस्टर के साथ रैली निकली गई।विभागध्यक्ष डॉ. वी के मनवानी के निर्देशन मे डॉ. सौरभ साहू डॉ. दिव्या बाजपेई व डॉ. विवेक देवांगन व प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के सहयोग से ये रचनात्मक कार्य सफ़ल हुआ। गौरतलाब है कि गांवो में आयोडीन की कमी से घैंगा बीमारी के काफ़ी मरीज़ पाए जाते हैं जिससे उनका पूरा शरीर प्रभावित होता है और थोड़ी सी जागरूकता से इससे आसानी से बचा जा सकता है।

भाजपा में शामिल हुए सामरी विधायक चिंतामणि महाराज

■ ओम माथुर ने कराया पार्टी में प्रवेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगातार झटका लग रहा है। आज फिर कांग्रेस को जोर का झटका लगा है। सरगुजा संभाग के सामरी के विधायक चिंतामणि महाराज ने आज बीजेपी में प्रवेश कर लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने उन्हें भाजपा में प्रवेश करवाया। उन्होंने चिंतामणि महाराज को माला पहनाकर भाजपा में घर वापसी कराया। विधायक चिंतामणि महाराज को इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर वो नाराज चल रहे थे।

इस बार कांग्रेस ने सामरी से उनका टिकट काटकर विजय पैकरा को प्रत्याशी बनाया है। इस वजह से वो नाराज चल रहे थे। टिकट कटने से महाराज के बागी तेवर दिख रहे थे और वो भाजपा के संपर्क में थे। बीते रविवार को बृजमोहन अग्रवाल हेलीकाप्टर से कुसमी एवं श्रीकोट पहुंचे थे। चिंतामणी महाराज ने भाजपा में शामिल होने के लिए अंबिकापुर से सांसद प्रत्याशी बनाए जाने की शर्त रखी थी। उन्होंने खुद खुलासा किया था कि बीजेपी उन्हें सांसद का टिकट देने तैयार है।

दो दिन पहले ही रविवार को महाराज भाजपा के हेलीकाप्टर से रायपुर से कुसमी आए थे। यहां भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया था। चिंतामणी महाराज ने यह स्पष्ट नहीं किया था कि वो भाजपा में जा रहे हैं। इसे लेकर तरह-तरह की चर्चा भी हो रही थी। बीते 7 दिन से उनकी बीजेपी नेताओं से बातचीत चल रही थी। चर्चा थी कि उन्हें सांसद टिकट का आश्वासन मिलने पर ही वो बीजेपी में शामिल होंगे। इसे लेकर विधायक बृजमोहन अग्रवाल से बातचीत भी हुई थी। फिर मामला कुछ दिन के लिए टल गया था। आज मंगलवार को राजमोहनी भवन में आयोजित कार्यक्रम में महाराज ने भाजपा का दामन थाम लिया है। वो अपने समर्थकों के साथ भाजपा में प्रवेश किए। टिकट कटने से नाराज होने की खबरों के बीच चिंतामणी महाराज की डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से फोन पर बातचीत हुई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि महाराज कांग्रेस में ही रहें तो बेहतर है। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है।

चिंतामणि महाराज लगभग 11 साल पहले बीजेपी में थे। भाजपा से उपेक्षित के आरोप पर उन्होंने 2008 में सामरी विधानसभा से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा था पर हार गए थे। इसके बाद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। साल 2013 में उन्हें कांग्रेस ने लुंड्रा से टिकट दिया था और वे विधायक बने। 2018 में दोबारा चिंतामणि महाराज को कांग्रेस ने सामरी से प्रत्याशी बनाया और वे दूसरी बार विधायक बने। अब फिर बीजेपी में उनकी घर वापसी हो गई है।

चिंतामणी महाराज छत्तीसगढ़ के संत गहिरा गुरु के बेटे हैं। सरगुजा सरगुजा संभाग समेत प्रदेश भर में उनके समाज के अनुयायी हैं। ऐसे में बीजेपी में उनके प्रवेश करने से सरगुजा संभाग की 6 सीटों पर सीधा असर पड़ सकता है। बीजेपी यहां से आगे हो सकती है। क्योंकि वर्तमान में संभाग की 14 की 14 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। उनके इस कदम से कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है।

मेरी यह घर वापसी हैं : चिंतामणि

अंबिकापुर। सामरी से कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज टिकट कटने से नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने एक बार फिर भाजपा का दाम थाम लिया है। उन्हें भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने गमछा पहनाकर फिर से घर वापसी करवाया। इस दौरान महाराज ने कहा कि वे पहले भाजपा में ही थे लेकिन जिन लोगों पर भरोसा करके वे कांग्रेस में गए थे उन्होंने धोखा दिया इसलिए आज वे घर वापसी कर रहे हैं।

अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में आयोजित कार्यक्रम में चिंतामणि महाराज ने कहा कि संत समाज की इच्छा के अनुरूप वे भाजपा में वापस लौट रहे हैं। भाजपा से उन्होंने समाज के संरक्षण के बहाने फिर से अपनी शर्त सामने रखी। उन्होंने कहा कि पहले एक बार उनके साथ धोखा हुआ है इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा ने उन्हें लोकसभा की टिकट देने का आश्वासन दिया है।

भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि चिंतामणि के भाजपा में वापस आने से सरगुजा क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। उन्होंने चिंतामणि महाराज के साथ संत समाज के लोगों को आश्वस्त किया कि जिस भरोसे के साथ संत समाज आज उनके साथ है, उस भरोसे को भाजपा टूटने नहीं देगी। उन्होंने चिंतामणि महाराज से हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि चिंतामणि महाराज ने ऐसे लोगों पर भरोसा कर लिया था जिन्हें भरोसे का सम्मेलन आयोजित करना पड़ रहा है।

5 साल में छत्तीसगढ़ का नहीं हुआ विकास : धर्मेंद्र प्रधान

रायगढ़। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधान से कहा कि पिछले पांच साल में भूपेश सरकार ने गांधी परिवार के एटीएम को ही भरने का काम किया। जो पैसा यहां की जनता को मिलना चाहिए था उसे गांधी परिवार के पास भेजा।

छत्तीसगढ़ में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेजी के नेतृत्व में साल 2000 में छत्तीसगढ़ बना। लेकिन इसका असली विकास साल 2003 से शुरू हुआ, जब यहां भाजपा की सरकार बनी। तब से लगातार छत्तीसगढ़ का विकास हुआ लेकिन यहां की जनता ने साल 2018 में भाजपा को सेवानिवृत किया और कांग्रेस के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंप दी। इसके लिए मैं यहां की जनता से माफी मांगता हूं।

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा यहां की जनता की है। सैकड़ों करोड़ रुपये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ जिले के लिए भेजते हैं। ताकि रायगढ़ के किसानों, आदिवासियों, गरीबों, महिलाओं का विकास हो सके, लेकिन यहां की भूपेश सरकार डीएमएफ फंड से रायगढ़ का विकास ना करके गांधी परिवार का खजाना भर रही है। इसी वजह से रायगढ़ के कई अधिकारी जेल में हैं। प्रधान ने कहा कि माफियाओं को जेल भेजना अभी शुरू हुआ हैं। दिसंबर में सरकार बनने के बाद ये सिलसिला और तेज होगा।

पीएम मोदी ने 16 लाख गरीबों के लिए छत्तीसगढ़ में आवास बनाने के लिए रुपये भेजे। पहले गरीबों को घर बनाने के लिए 75 हजार रुपये दिए जाते थे लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद अब हर गरीब को डेढ़ लाख रुपये दिया जा रहा है। प्रधान ने कहा कि प्रदेश की भूपेश सरकार 16 लाख गरीबों के घरों को पूरा नहीं होने दे रही हैं। रायगढ़ के किसानों का युवाओं का महिलाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां की जनता पांच साल में समझ चुकी है। अब यहां बदलाव की बयार बह रही हैं। दिसंबर में यहां भाजपा की सरकार बनेगी।

बता दें कि रायगढ़ विधानसभा सीट पर 17 नवंबर को दूसरे चरण में चुनाव है। भाजपा ने रायगढ़ सीट पर ओपी चौधरी को टिकट दिया है। जबकि कांग्रेस ने प्रकाश नायक को टिकट दिया है। लैलुंगा विधानसभा से भाजपा ने महिला प्रत्याशी सुनीता राठिया को टिकट दिया है। कांग्रेस के चक्रधर सिंह धीगर चुनाव लड़ रहे हैं। धरमजयगढ़ से हरीश चंद्र राठिया की टक्कर कांग्रेस के लालजीत सिंह राठिया से होगी। खरसिया से भाजपा ने महेश साहू को उतारा है। यहां से मंत्री उमेश पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं।

संक्षिप्त समाचार

2 को कांकेर व 4 नवंबर को दुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नवम्बर को एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे है। इस दौरान वे कांकेर जिला में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा का घोषणा पत्र जारी करेंगे। 2 नवंबर के बाद पीएम मोदी 4 नवंबर को दुर्ग जिले में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक़ 14 नवंबर को वे एक बार फिर से प्रदेश का दौरा कर सकते है, इस दौरान प्रधानमंत्री रायपुर में रोड शो भी कर सकते हैं।

खड़गे आज आएंगे छत्तीसगढ़, महासमुंद व जगदलपुर में करेंगे चुनावी सभा

रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे एक बार फिर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे है, इस दौरान वे महासमुंद और जगदलपुर में जनसभा को सम्बोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खडगे एक नवंबर की सुबह राजधानी रायपुर पहुंचेंगे, इसके बाद वे महासमुंद और जगदलपुर जिलों में चुनाव प्रचार करने के लिए निकल जाएंगे जहां वे आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगे। उल्लेखनीय हैं कि 20 विधानसभा क्षेत्रों में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 24 घंटा पहले वहां प्रचार - प्रसार थम जाएगा। प्रदेश में अपनी सत्ता बनाने के लिए भाजपा और कांग्रेस के साथ अन्य अन्य पार्टियों के प्रत्याशी जमकर चुनाव प्रचार-प्रसार कर रहे है।

कांग्रेस ने किया 17 घोषणा, भाजपा एक गारंटी तो दें : बघेल

रायपुर। बस्तर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेश बघेल ने पत्रकारों से संक्षिप्त चर्चा में कहा कि हमने 17 घोषणाएं की हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने गारंटी भी दी है। भाजपा को कम से कम एक गारंटी देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को उड़ान योजना के तहत बस्तर को जोडने वाली उड़ानों को रद्द करने और छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों को रद्द करने पर संज्ञान लेना चाहिए।

किसान कांग्रेस दुर्ग जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी ने पार्टी से दिया इस्तीफा

भिलाई। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। किसान कांग्रेस के दुर्ग जिलाध्यक्ष राजेश चौधरी ने टिकट काटने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया है। उल्लेखनीय हैं कि राजेश चौधरी वैशाली नगर से टिकट की मांग कर रहे थे, पर पार्टी ने उस क्षेत्र से मुकेश चंद्राकर का नाम घोषित कर दिया। इसी बात से नाराज होकर राजेश चौधरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। राजेश चौधरी के पार्टी छोडने से खलबली मच गई है।

महंत ने किया अरविंद दीक्षित वार्ड में जनसंपर्क

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी महंत रामसुंदर दास ने मंगलवार को नगर निगम रायपुर के सभापति प्रमोद दुबे के साथ ले. अरविंद दीक्षित वार्ड क्रमांक 56 में जनसंपर्क किया। इस दौरान वार्ड के लोगों ने महंत जी का आरती उतारकर तो किसी ने पैर छूकर व तिलक लगाकर उनका स्वागत किया और कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने का भरोसा दिलाया। महंत ने लोगों से कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे, वार्ड पार्षद, जोन अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड/ब्लॉक के पदाधिकारी समेत अनेक कांग्रेस जन शामिल हुए।

70 विधानसभा सीटों के लिए 1219 प्रत्याशियों ने भरे 1985 नामांकन पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन सोमवार को पूरा हुआ। 70 विधानसभा सीटों के लिए 1219 प्रत्याशियों ने 1985 नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन के आखिरी दिन 1245 नॉमिनेशन किए गए। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी।

2 नवंबर नाम वापसी की अंतिम तारीख- छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग की कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। 17 नवंबर को यहां चुनाव होंगे। दूसरे चरण के नामांकन की जांच 31 अक्टूबर को होगी। प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। 17 नवंबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के कुल 1 करोड़ 63 लाख 14 हजार 479 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिसमें 81 लाख 41 हजार 624 पुरुष मतदाता और 81 लाख 72 हजार 171 महिला मतदाता है। 684 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल है।

दूसरे चरण में इन सीटों पर चुनाव- दूसरे चरण में भरतपुर-सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव,

लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डोंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। पहले और दूसरे दोनों चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी।

गजनी तो 4 को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं? भूल गये है अच्छे दिन लाने का वादा : कांग्रेस

■ देवेंद्र फडणवीस भाजपा की झूठ बोलो प्रतियोगिता में शामिल होने आये थे प्रतियोगिता में जीतेगा तो मोदी ही

रायपुर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भाजपा के झूठ बोलो प्रतियोगिता में शामिल होने आए थे लेकिन देवेंद्र फडणवीस भूल गये की वो कितना भी झूठ बोल ले आखिर में प्रतियोगिता में जीत तो मोदी की ही होगी। मोदी के आगे भाजपा के सारे नेताओं की झूठ फीकी हो जाती है।प्रदेश की जनता के कान भाजपा नेताओं के जुमला और झूठ को सुन-सुन के पक चुकी है। मन की बात हो या चुनाव का मंच झूठ परोसने के अलावा कुछ आता भी नही है।

ठाकुर ने कहा कि गजनी तो 4 नवम्बर को छत्तीसगढ़ आ रहे है? जो जनता से किये हर वादे को भूल चुके हैं।15-15 लाख रुपया खाता में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम होगी, 30 रु35 रु में डीजल-पेट्रोल मिलेगा, हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, एक सैनिक के बदले पाक के दस सैनिको का सिर काट कर लायेंगे, 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार उपज की लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलेगा, युवाओं को दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, 100 दिन में महंगाई कम होगी। बेटी सुरक्षित होगी। बुलेट ट्रेन चलेगा सहित अनेक वादा किया गया था और सत्ता मिलते ही उन वादों को जुमला बताकर जनता का उपहास उड़ाया गया है। प्रदेश में भी भाजपा ने वादाखिलाफी किया है तो भूलने की बीमारी तो भाजपा नेताओं को है जैसे गजनी को था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। 2018 में किए वादों में से 95 प्रतिशत वादों को पूरा की है और 2023 के चुनाव में जो वादा किया जा रहा है वह भी पूरा किया जाएगा। जनता की खुशहाली से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के हित में घोषणा कर रही है और भाजपा के पास प्रदेश की जनता के लिए ना कोई विजन है, ना कोई योजना है, सिवाय जुमला के।

दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान के लिए किए जा रहे प्रयासों का उठाएं अधिकतम लाभ : कंगाले

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने रेडक्रास भवन रायपुर के सभाकक्ष में दिव्यांग मतदाताओं के सुगम मतदान विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन में दिव्यांग तथा वृद्ध मतदाताओं को मतदान में सुविधा प्रदान करने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दिव्यांगों तथा वृद्ध मतदाताओं के लिए मतदान की प्रक्रिया को अधिक सुगम बनाते हुए इस वर्ग के मतदाताओं को घर बैठे ही डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने का विकल्प दिया गया है। इसके साथ ही यदि दिव्यांग मतदाता मतदान करने के लिए मतदान केन्द्र तक आने के लिए वाहन की सुविधा चाहेंगे तो उन्हें निर्वाचन आयोग की तरफ से सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस सुविधा के लिए ऐसे मतदाताओं को पहले अपना पंजीयन कराना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती कंगाले ने बताया कि मतदान दिवस को दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के सहयोग हेतु एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। मतदान केंद्र पर मतदान के लिए आने वाले दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ

मतदाताओं को कतार में खड़े न रहना पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग पहले करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ईवीएम मशीन पर प्रत्याशियों का नाम ब्रेल लिपि में भी मुद्रित कराया जा रहा है। मतदान कक्ष में दिव्यांग मतदाताओं की विशेष जरूरतों के संबंध में मतदान कर्मियों को संवेदनशीलता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य स्तरीय संगोष्ठी को कलेक्टर श्री सर्वेश्वर भूरे ने भी संबोधित किया। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्र पर स्थापित होने वाले मतदाता सहायता बूथ (वीएबी) की स्थिति की जानकारी दिव्यांग मतदाताओं को देने के लिए संकेतक चस्पा किए जा रहे हैं। उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए तैयार सक्षम मोबाइल एप का उल्लेख करते हुए इसे बहुउपयोगी बताया।

राज्य स्तरीय मतदाता आइकन श्री चित्रसेन साहू ने आयोग के प्रयासों का उल्लेख करते हुए इसे दिव्यांग मतदाताओं के लिए बहुत कारगर कदम बताया। उन्होंने अपने अनुभवों का उल्लेख करते हुए बताया कि अब मतदान करना सही मायनों में उत्सव हो गया है। पहले मतदान केन्द्र तक जाना और कतार में खड़े होकर मतदान करना दिव्यांगों के लिए बड़ी समस्या होती थी। निर्वाचन आयोग द्वारा बीते कुछ वर्षों में सुगम निर्वाचन के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वो अत्यंत सराहनीय हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोग के इन प्रयासों के कारण शत-प्रतिशत दिव्यांग मतदाता मतदान करने के लिए आगे आएंगे।

संगोष्ठी में जिला स्तरीय मतदाता ऑइकॉन श्री पृथ्वी राज ने सक्षम एप की उपयोगिता का उल्लेख किया। उन्होंने इसे दिव्यांगों के लिए हाइटेक सुविधा बताते हुए अधिक से अधिक प्रसारित करने की बात कही। संगोष्ठी के दौरान दिव्यांग मतदाताओं के समक्ष इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सक्षम एप के उपयोग के संबंध में भी प्रस्तुति दी गई।

टीएस सिंहदेव को एप्पल (आईफोन) की ओर से मिला सुरक्षा संबंधित ईमेल

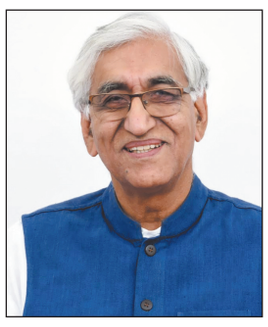

रायपर। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव को मंगलवार को उनकी ईमेल आईडी पर आईफोन की ओर से एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें आईफोन की ओर से अलर्ट जारी करते हुए बताया गया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के द्वारा उनके आईफोन को टारगेट किए जाने की संभावना है जिससे उनके फोन के डाटा के साथ समझौता हो सकता है।

उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने इस ईमेल की तुलना पेगासस जैसी घटना से करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए कुछ ही दिन शेष बचे हैं तब इस प्रकार का इमेल प्राप्त होना चिंता का विषय है यदि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीतिक संलिप्तता है तो यह भारत के लोकतंत्र और व्यक्ति की निजता का हनन है। उन्होंने कहा कि देश के सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्ति की निजता कि सुरक्षा भी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और यदि प्रकार की कोई घटना होती है तो यह शासन की डिजिटल सुरक्षा प्रणाली पर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को भी इस प्रकार के मेल प्राप्त हुए हैं और इस मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता करते हुए विस्तृत जानकारी दी थी कि उनके ऑफिस में सभी को इस प्रकार के ईमेल मिले हैं जो कि इस मामले को और गंभीर बना देता है।

फडणवीस ने बघेल को गजनी बोलकर छत्तीसगढ़ का किया अपमान : तिवारी

रायपुर। कल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजनी कहा, गजनी एक विलेन था उसकी तुलना छत्तीसगढ़ की जनता के दो तिहाई बहुमत से बनी सरकार के मुखिया से करना छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों के, युवाओं के, आदिवासियों सर्वसमाज के नायक है, वे राज्य की ओबीसी समाज का अभिमान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गजनी बोलकर देवेन्द्र फडणवीस राज्य के सर्वहारा वर्ग का अपमान किया है। देवेन्द्र फडणवीस चोरी की सरकार में उपमुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री बनाने के बाद वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे है। उक्त बातें एआईसीसी के प्रदेश कांग्रेस मीडिया पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ नेता राज्यसभा में उपनेता प्रतिपक्ष प्रमोद तिवारी ने राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहीं।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो जनता से किये अपने सारे वायदो को पूरा किया। हमारी सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र के 95 प्रतिशत वायदों को पूरा किया है। हम किसी भी जनप्रतिनिधि को गजनी की उपाधि देने के खिलाफ है लेकिन यदि फडणवीस वायदो को भूलने का आधार बनाते है तो उन्हें गजनी की तुलना मोदी जी से करनी चाहिये। जो जनता से किये हर वादे को भूल चुके हैं। 15-15 लाख रुपया खाता में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन में महंगाई कम

होगी, 30 रु. 35 रु. में डीजल-पेट्रोल मिलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाले गरीबो को हवाई यात्रा कराने का वादा किये थे, भारत के एक सैनिक के बदले पाक के दस सैनिको के सिर काट कर लाने का वादा किये थे। 2022 में किसानों की आय दोगुनी होगी, स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिश के अनुसार उपज की लागत मूल्य का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य मिलेगा। युवाओं को दो करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिलेगा, 100 दिन में महंगाई कम होगी। बेटी सुरक्षित होगी। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलेगा सहित अनेक वादा किया गया था और सत्ता मिलते ही उन वादों को जुमला बताकर जनता का उपहास उड़ाया गया है। कांग्रेस जो कहती है उसको पूरा करती है। 2018 में किए वादों में से को पूरा की है और 2023 के चुनाव में जो वादा किया जा रहा है वह भी पूरा किया जाएगा। जनता की खुशहाली से भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के हित में घोषणा कर रही है और भाजपा के पास प्रदेश की जनता के लिए ना कोई विजन है, ना कोई योजना है, सिवाय जुमला के। तिवारी ने कहा कि देवेन्द्र फडणवीस चोरी की सरकार में उपमुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री से उपमुख्यमंत्री बनाने के बाद वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे है। इस लिये वे अनर्गल बयानबाजी कर रहे है। चोरी की सरकार में उपमुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस को कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार से सीखना चाहिये कि जनता से किया गया वायदा कैसे निभाया जाता है। कांग्रेस ने 2018 में जनता से जो वायदा किया था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसमें 95 प्रतिशत से अधिक वायदों को पूरा किया। यही कारण है प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।

भूटान-चीन की नजदीकी से रहना होगा भारत को सतर्क

शोभना जैन

भारत के परंपरागत प्रगाढ़ पड़ोसी देश भूटान के विदेश मंत्री तांडी दोरजी की ताजा चीन यात्रा इस समूचे क्षेत्र के लिए बेहद अहम खबर है। चीन के साथ दूसरे छोर पर खड़े भूटान के लिए, जिसके साथ उसके राजनयिक संबंध भी नहीं हैं, ये पड़ाव न केवल भूटान के लिए और इस समूचे क्षेत्र के लिए बल्कि विशेष तौर पर भारत भूटान संबंधों के लिए दूरगामी परिणाम वाले माने जा रहे हैं। खबर है कि दोनों देश दशकों से चल रहे सीमा विवाद को खत्म करने के करीब पहुंच गए हैं। ऐसे भी संकेत हैं कि दोनों देश जल्द ही राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। निश्चय ही इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पहुंच भारत की चिंता बढ़ाती रही है और अब यह नया घटनाक्रम भारत के लिए चिंता और बढ़ाने वाला है। अगर चीन और भूटान के बीच सीमा को लेकर कोई समझौता होता है तो उसका सीधे तौर पर असर डोकलाम ट्राई-जंक्शन पर पड़ सकता है, जिसे लेकर 2017 में भारत और चीन की सेनाओं के बीच यहां 73 दिनों तक गतिरोध रहा था। गतिरोध तब शुरू हुआ था जब चीन ने उस इलाके में एक ऐसी जगह सड़क बनाने की कोशिश की थी, जिस पर भूटान का दावा था। चीन और भूटान के बीच सीमा वार्ता का 25वां दौर 23 और 24 अक्तूबर को बीजिंग में आयोजित किया गया। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच 1984 से शुरू हुई सीमा वार्ता सात वर्ष बाद हुई, जिसके दोनों ही देशों ने सकारात्मक परिणाम निकलने की बात कही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता के दौरान दोनों प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं ने चीन और भूटान की सरकारों के बीच सहयोग समझौते पर दस्तखत किए। यह सहयोग समझौता चीन-भूटान सीमा के निर्धारण और सीमांकन पर संयुक्त तकनीकी टीम (जेटीटी) की जिम्मेदारियों और कार्यों के बारे में है। चीन के साथ भूटान 400 किमी से अधिक लंबी सीमा साझा करता है और दोनों देश विवाद को सुलझाने के लिए साल 1984 से अब तक 25 दौर की सीमा वार्ता कर चुके हैं। दो इलाकों को लेकर चीन और भूटान के बीच ज्यादा विवाद है, उनमें से एक भारत-चीन-भूटान ट्राई-जंक्शन के पास 269 वर्ग किमी का इलाका और दूसरा भूटान के उत्तर में 495 वर्ग किमी का जकारलुंग और पासमलुंग घाटियों का इलाका है। चीन भूटान को 495 वर्ग किमी वाला इलाका देकर उसके बदले में 269 वर्ग किमी का इलाका लेना चाहता है। भूटान की उत्तरी सीमा पर जिन दो इलाकों पर चीन का दावा है, इनमें से एक चुम्बी घाटी का है, जिसके नजदीक डोकलाम में भारत और चीन के बीच गतिरोध हुआ था। चीन इस इलाके के बदले में भूटान को दूसरा विवादित इलाका देने को तैयार है, जो चुम्बी घाटी के इलाके से कहीं बड़ा है। भारत के लिए चिंता की बात ये है कि चीन जो इलाका भूटान से मांग रहा है, वो भारत के उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर या %चिकन्स नेक% के करीब है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंचने के लिए भारत का मुख्य रास्ता है। अगर चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब आता है, तो यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि यह पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी के लिए खतरा बन सकता है और एक बड़ी सामरिक चुनौती होगी। 25 दौर की बातचीत के बाद चीन और भूटान कह रहे हैं कि वे सीमा निर्धारण के करीब हैं। वे जिस बात पर सहमत हुए हैं, वह यह है कि दोनों पक्ष सीमांकन पर काम करेंगे। तो ये काम अभी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझा लिया है। विदेश नीति के एक विशेषज्ञ मानते हैं कि भूटान कह चुका है कि ट्राई-जंक्शन मुद्दे को त्रिपक्षीय तरीके से हल करना होगा और भूटान ऐसा कोई समझौता नहीं करेगा, जो भारत के हित में न हो। गौरतलब है कि भूटान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य देश के साथ कोई राजनयिक संबंध नहीं हैं। अगर भूटान सिर्फ चीन को चुनता है तो भारत-भूटान संबंधों में कुछ दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये यह भारत के लिए अस्वीकार्य होगा और इससे कूटनीतिक समस्याएं पैदा होंगी।

संसद के अधिकार क्षेत्र में फिर दखल

अजय सेतिया

न्यायपालिका और विधायिका में टकराव का एक और मुद्दा खड़ा हो गया है। सुप्रीमकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के राज्यसभा से निलंबन संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रही है। कायदे से यह याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड ने इस याचिका को स्वीकार करके सुनवाई शुरू कर दी है। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी ने अदालत में अपनी आपत्ति दायर की थी कि वह सदन के भीतर की किसी कार्रवाई पर याचिका स्वीकार नहीं कर सकती। क्या यह याचिका उप-राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उन बयानों की वजह से स्वीकार की गई, जिनमें धनखड़ ने सुप्रीमकोर्ट के जजों के नियुक्ति संबंधी क़ानून को रद्द करने की आलोचना की थी। धनखड़ ने कुछ महीने पहले कोलिजियम सिस्टम की आलोचना करते हुए कहा था कि जजों की नियुक्ति के संबंध में संसद ने जो क़ानून बनाया था, सुप्रीमकोर्ट को उसे रद्द करने का अधिकार नहीं था, इस पर चर्चा होनी चाहिए।

राघव चड्ढा पहली बार राज्यसभा के सांसद बने हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनकी संसदीय यात्रा 2020 से शुरू हुई थी, जब वह दिल्ली से विधायक चुने गए, दो साल बाद 2022 में वह राज्यसभा सदस्य बन गए। अनुभवहीनता कहें या खुराफाती दिमाग कि जब 7 अगस्त की रात को दिल्ली सेवा बिल पास हो रहा था, तो उन्होंने बिल को सलेक्ट कमेटी में भिजवाने के लिए पेश किए गए अपने प्रस्ताव में पांच ऐसे नाम जोड़ दिए, जो वास्तव में सत्ताधारी गठबंधन के सांसद थे। इनमें तीन भाजपा के, एक बीजद का और एक अन्नाद्रमुक का सांसद था। इन पांचों ने राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को शिकायत की थी। इस पर अमित शाह ने कहा- मोशन पर चड्ढा ने 5 सांसदों के फर्जी दस्तखत लगाए हैं, दो मेंबर्स कह रहे हैं कि दस्तखत उन्होंने नहीं किए, इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए। डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने कहा कि उन्हें भी 4 सदस्यों की शिकायत मिली है।

जिस पर मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया, लेकिन राघव चड्ढा ने प्रेस कांफ्रेंस करके आरोपों को निराधार बताया। राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा लगातार दुष्प्रचार कर रही है, झूठ बोल रही है। राज्यसभा के बुलेटिन में कहीं भी दस्तखत, फर्जीवाड़ा, फोर्जरी, जालसाजी जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर भाजपा के पास प्रुफ है, तो वह इसे दिखाए।

राघव चड्ढा का यह बयान चोरी और सीनाजोरी का मामला था। जो मामला विशेषाधिकार समिति को सौप दिया गया था, उस पर सदन के बाहर चर्चा नहीं की जानी चाहिए थी। इसलिए सदन के नेता पीयूष गोयल ने 11 अगस्त को तब तक उनकी सदस्यता निलंबन का प्रस्ताव रखा, जब तक विशेषाधिकार समिति फैसला नहीं करती। यह एक सामान्य सी प्रक्रिया है, सदन के भीतर की घटना और सदन के नियमों का मामला है। राघव चड्ढा ने 10 अक्टूबर को सदन से अपने निलंबन को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। 31 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान सुप्रीमकोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणियां की हैं, वे संसद के अधिकारों को चुनौती देने वाली हैं। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट का एक फैसला याद आता है। जुलाई 1993 में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने नरसिंह राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा था। प्रस्ताव पास होना तय था, क्योंकि सरकार अल्पमत में थी। नरसिंह राव सरकार ने 50- 50 लाख रूपए में पांच सांसद खरीदे और अपनी सरकार बचा ली।1995 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस घूसकांड का संसद के भीतर सनसनीखेज खुलासा किया। वाजपेयी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद शैलेंद्र महतो को लेकर सामने आए।

शैलेंद्र महतो ने संसद के सामने स्वीकार किया कि शिबू सोरेन समेत उनकी पार्टी के तीन सांसदों ने नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए 50-50 लाख रुपए की घूस ली थी। इसके बाद इस मामले की लंबी सीबीआई जांच और सुनवाई चली। घूस का पैसा बाकायदा बैंक खातों में जमा था, जिस पर आयकर विभाग ने आयकर का दावा भी किया था। हालांकि लंबी सुनवाई के बाद उसे चंदा बता कर रफा दफा कर दिया गया था।

इस घूसकांड के बारे में सीबीआई की चार्जशीट में कुछ सनसनीखेज खुलासे हुए थे। लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीमकोर्ट ने यह कहते हुए उन सभी सांसदों को बरी कर दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को संसद के भीतर भाषण या वोट देने के मामले में सुप्रीमकोर्ट कुछ नहीं कर सकती। इसलिए संसद से बाहर दी गई रिश्वत और संसद के भीतर हुई वोटिंग को वह जोड़ कर नहीं देख सकती।

सुप्रीमकोर्ट के इसी फैसले के अधिकार पर राघव चड्ढा की अपील अस्वीकार होनी चाहिए थी। लेकिन राघव चड्ढा के वकील की बहुत ही लचर दलील पर उनकी याचिका स्वीकार कर ली गई कि सभापति किसी भी सांसद का निलंबन अनिश्चितकालीन नहीं कर सकते। जबकि निलंबन तो क्या 2005 में लोकसभा के दस और राज्यसभा के एक सांसद की सदस्यता भी खत्म हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल वेंकटरमनी ने कोर्ट में कहा कि निलंबन सभापति ने नहीं किया, संसद में प्रस्ताव पास करके हुआ है। इसलिए यह सदन की कार्यवाही का सवाल है। कोर्ट का इस मसले पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं बनता, कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन चीफ जस्टिस चन्द्रचूड ने उनकी एक नहीं सुनी। ठीक इसी तरह सुप्रीमकोर्ट महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को भी धमकी दे चुका है। कोर्ट ने इतना जरुर कहा कि वह विशेषाधिकार हनन के विस्तृत विषय या विशेषाधिकार कमेटी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगी। कोर्ट ने कहा कि उसके सामने जो विचार का मसला है- वह अनिश्चित काल तक निलम्बन का है। इस पर राघव चड्ढा के वकील की एक और लचर दलील यह थी कि राघव चड्ढा अगर 60 दिन तक हाऊस में नहीं गए तो सीट खाली घोषित हो सकती है, ऐसे में कैसे अनिश्चित काल तक सस्पेंड किया जा सकता है। यह लचर दलील इसलिए है कि सदन ने खुद प्रस्ताव पास करके उन्हें सस्पेंड किया है, वह अपनी मर्जी से गैरहाजिर नहीं हैं, इसलिए यह नियम उन पर लागू ही नहीं होता। राघव चड्ढा के वकील की दलील है कि नियम 255 और 256 उस सत्र से परे निलंबन का अधिकार नहीं देते हैं। हालांकि नियम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं। अदालत ने कहा कि वह कानून को स्पष्ट करेगा कि क्या विशेषाधिकार समिति के अंतिम निर्णय तक किसी सांसद को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब यह भी संसद के अधिकारों और नियमों में दखल है।

सुप्रीमकोर्ट के जज की टिप्पणी बहुत ही हास्यस्पद भी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि विशेषाधिकार समिति के निर्णय लेने की कोई समय सीमा नहीं है, अगर समिति वर्तमान सदन के कार्यकाल तक निर्णय नहीं लेती है तो क्या होगा? क्या इसका मतलब यह है कि निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का उनका अधिकार अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को इतना भी नहीं पता कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म नहीं होता, लोकसभा की तरह राज्यसभा भंग भी नहीं होती। सांसद का कार्यकाल खत्म होता है। और राज्यसभा के सांसद का निर्वाचन क्षेत्र भी नहीं होता। राघव चड्ढा की दलील है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि क्या वह कोर्ट के सामने और सभापति के सामने अपनी गलती के लिए माफी मांगने को तैयार हैं, तो राघव चड्ढा के वकील तुरंत तैयार हो गए। क्या यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि जब गलती नहीं की, तो माफी मांगने पर सहमति क्यों। हालांकि अटार्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि निलंबन के आदेश को रद्द करना स्पीकर या चेयरपर्सन के अधिकार क्षेत्र में नहीं हो सकता है, क्योंकि आदेश सदन के एक प्रस्ताव के बाद आया था।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-29)

गतांक से आगे...

जिसकी भोग कामनाएँ क्षीण हो चुकी हैं, आकांक्षाएँ समाप्तप्राय हैं तथा बुद्धि जागरूक है, उसी को वेदान्त का उपदेश प्राज्ञ गुरु प्रदान करे। अविद्यारूपी विकार का कोई अस्तित्व नहीं। जैसे सूर्योदय होने पर दिवस, दीपक से प्रकाश तथा पुष्प से सुगन्धि की स्थिति का होना निश्चित है, वैसे ही चैतन्य पर संसार विद्यमान है।

आसानी से इसका स्वरूप देखने में नहीं आता, परन्तु दिखाई देते ही यह नाश को प्राप्त होती है। भेद दृष्टि का होना ही अविद्या है, इसका सर्वथा त्याग करना ही कल्याणप्रद है। वस्तुत: माया का अस्तित्व है ही नहीं- सब कुछ ब्रह्ममय है, ऐसी दृढ़ निश्चय से की गई आन्तरिक भावना ही मोक्षप्राप्ति का उपाय है।

हे मुनिश्रेष्ठ! माया द्वारा जो नहीं पाया जाता, वह अक्षय पद के नाम से जाना जाता है। हे द्विज ! इस माया की उत्पत्ति किससे हुई, इसके बारे में तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए; अपितु विचार यही रहे कि किस प्रकार इसे नष्ट करूँ ? इसके क्षीण होकर विनष्ट हो जाने पर तुम क्षयरहित पद को पा सकोगे। इसके प्रकट होने का लक्षण इसका स्वरूप और इसके नष्ट करने के उपाय पर विचार करते हुए इस रोग के मूलकारण के निदान का प्रयास करना चाहिए। जिससे यह तुम्हें आवागमन के जन्मचक्र में बारम्बार न डाले और चित् रूपी समुद्र निर्मल आत्म- स्पन्दन से विभासित हो सके। यह चिदात्मा अविभाजित रूप वाली है, अपने भीतर इस प्रकार का दृढ़निश्चय करना चाहिए। यह चिदात्मा चिन्मय सागर में कुछ क्षोभयुक्त हो रही है। सागर में लहरों की तरह निर्मल चिन्मय लहरें उठ रही हैं। आकाश सरोवर में जिस प्रकार वायु स्वयमेव लहराती है, उसी प्रकार अपनी आत्मा में आत्मबल से आत्मा तरंगित होती है। सर्वशक्तिमान् सत्ता द्वारा इस प्रकार की दैवी स्फुरणा क्षण मात्र के लिए होती है। जिस चेतनशक्ति को देश, काल और क्रियाशक्ति चलायमान करने में अक्षम है, वही चेतनशक्ति अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानकर उच्च अनन्त पद पर प्रतिष्ठित है। यह चेतन शक्ति अज्ञान स्थिति में सीमित सी होकर रूप भावना वाली होती है। उस विलक्षण परमसत्ता में जब रूप की भावना समाविष्ट होती है। उस समय उसके साथ नाम और संख्या आदि उपाधियाँ जुड़ जाती हैं।

हे ब्रह्मन् ! चेतनशक्ति का वह रूप जो देश, काल और क्रिया का आश्रयरूप है तथा विकल्परूप को ग्रहण करने वाला है, वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। पुन: वही वासनात्मक चिन्तन से अहंकाररूप कहा जाता है। जब अहंकार भी निश्चयात्मक और दोषपूर्ण हो जाता है, तो बुद्धि कहलाता है। बुद्धि भी जब संकल्परूप में परिणत हो जाती है, तो मननशील मन का रूप धारण करती है। मन के गहरे विकल्प में डूबने पर धीरे-धीरे इन्द्रियस्वरूप की झलक मिलती है। मेधावी पुरुष हस्तपाद युक्त स्थूल शरीर को ही इन्द्रिय मानते हैं।

क्रमश: ...

छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस

1 नवंबर इस तारीख का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। इस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फ़ैसला लिया गया था। 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत के छह अलग-अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य-प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। ये छह राज्य एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन छह राज्यों के अलावा साल 1956 में 1 नवंबर के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहचान दी गयी थी।

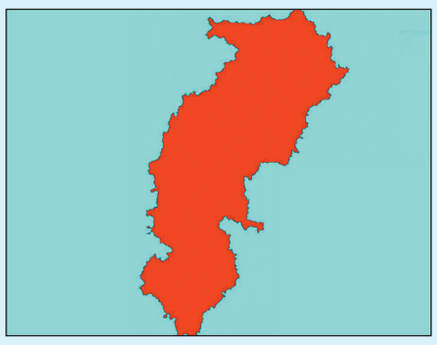

छत्तीसगढ़- भगवान श्री राम का ननिहाल दक्षिण कौशल प्रांत की 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के रुप में स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ एक प्राचीन नाम नहीं है, इस नाम का प्रचलन 18 सदी के दौरान मराठा काल में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ आज 01 नवंबर 2023 को अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1956 में इस प्रान्त का विलय वर्तमान मध्य-प्रदेश में कर दिया गया था। लेकिन, बाकी राज्यों की तरह मध्य-प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तत्कालीन समय इसमें 36 गढ़ समाहित थे, और यहाँ पर सभी लोग छत्तीसगढ़ी और गोंड भाषा बोलते थे। जिसके चलते छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग स्वतंत्रता से पहले ही उठ रही थी। लेकिन तब इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। बाद में 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब अजीत जोगी को इसका पहला मुख्यमंत्री बनाया गया।

मध्यप्रदेश- देश का दिल कहे जाने वाला राज्य मध्यप्रदेश आज 01 नवंबर 2023 को अपना 68वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही हुई थी। भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की स्थापना तत्कालीन भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही थीं। जिसका मुख्य कारण था चार प्रान्त- मध्य प्रांत, पुराना मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल को जोड़कर ही एक राज्य बनाना, लेकिन असल में इन बड़े प्रान्तों में रहने वाली जनता अलग-अलग विचार, जीवनशैली, खान-पान, रहन-सहन, लोक संस्कृति और आचार-विचार की थी, बहुत-सी बहस और विचार-विमर्श के बाद आखिरकार मध्य-प्रदेश बना। पुनर्गठन के पहले इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। 1 नवंबर,1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पं. रविशंकर शुक्ल का लाल परेड ग्राउंड पर पहला भाषण हुआ था।

पंजाब और हरियाणा- युनानियों, मध्य एशियाईओं, अफ़ग़ानियों और ईरानियों के लिए ऐतिहासिक तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश-द्वार रहे पंजाब स्वतंत्रता के बाद बड़े राज्य के रुप में संगठित था, राज्यों के पुनर्गठन पर फैसला लिया जा रहा था, तब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा (वर्तमान में) और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसके हिस्सा थे। लेकिन सन 1950 से भाषायी (पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी) आधार पर उठी राज्यों की मांग के चलते पंजाब पुनर्गठन विधेयक, 1966 के अनुसार 1 नवंबर, 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में एक नये राज्य का उदय हुआ। अब पंजाबी भाषी सिक्ख पंजाब, हिंदी भाषी हिंदू हरियाणा का हिस्सा बन गए। जहां पहाड़ी बोली जाती थी, उस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब, दोनों ने ही अपना अधिकार जताया। इसलिए, चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया जो कि दोनों राज्यों की राजधानी के रूप में जाना जाता है।

बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंसा

सुबीर भौमिक

बांग्लादेश में बीते शनिवार को विपक्ष की विरोध रैली के दौरान भड़की हिंसा दक्षिण एशिया के इस सबसे युवा देश में हिंसक चुनावी मौसम की शुरुआत हो सकती है। इस हिंसा में कम से कम एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और 40 पुलिसकर्मियों सहित 200 से अधिक लोग घायल हो गए। चिंता की बात है कि अब यह हिंसा मुल्क के अन्य हिस्सों में भी फैल रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के इस्लामी विपक्षी गठबंधन ने तीन बार से सत्ता में रही अवामी लीग को हटाने के लिए करो या मरो के रूप में यह विरोध रैली आयोजित की थी। अब इसने अपनी एक सूत्री मांग के समर्थन में तीन दिनों के लिए देश में पूर्ण परिवहन नाकाबंदी का आह्वान किया है। उसकी मांग है कि सत्तारूढ़ अवामी लीग इस्तीफा दे और जनवरी में होने वाले संसदीय चुनाव कराने के लिए एक तटस्थ कार्यवाहक प्रशासन को कार्यभार संभालने की अनुमति दे। यह नाकाबंदी 31 अक्तूबर से दो नवंबर तक के लिए निर्धारित है। वरिष्ठ बीएनपी नेता मिर्जा अब्बास कहते हैं, यदि अवामी लीग सत्ता में बनी रहती है, तो देश में केवल एक दल का शासन होगा। इसलिए यह आंदोलन सिर्फ अवामी लीग को सत्ता से बेदखल करने के लिए नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के नवोदित लोकतंत्र को बचाने के लिए है।

अवामी लीग की केंद्रीय समिति की सदस्य तराना हलीम प्रतिवाद करते हुए कहती हैं- बीएनपी-जमात लोकतंत्र के विरोधी हैं। 2001 में जब वे सत्ता में आए, तो मेरे अलावा हमारे कई नेताओं पर उन्होंने

हमले किए। उन्होंने 2004 में शेख हसीना सहित हमारे पूरे केंद्रीय नेतृत्व को खत्म करने तक की कोशिश की। वे विरोधियों को खत्म करने की पाकिस्तानी शैली के सैन्यवाद में विश्वास करते हैं।

अवामी लीग के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है, जैसा कि विपक्षी इस्लामी गठबंधन के लिए भी है। बांग्लादेश पर कई किताबें लिखने वाले सुखरंजन दासगुप्त कहते हैं, यदि अवामी लीग जनवरी में होने वाले संसदीय चुनाव में हार जाती है, तो 2001-06 की तरह बीएनपी-जमात शासन के दौरान खून-खराबा होगा। हजारों पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपना कार्यक्षेत्र छोड़कर देश से भागना होगा। यदि विपक्ष सत्ता हासिल करने में सफल नहीं होता, तो यह निश्चित रूप से एक पार्टी के रूप में बीएनपी का अंत होगा।

दासगुप्त कहते हैं, पारंपरिक रूप से लंबे समय तक विपक्षी आंदोलनकारी भूमिका के कारण अवामी लीग सड़कों पर उतरने वाली एक शक्तिशाली पार्टी है। पर करीब 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के कारण अब यह सांगठनिक रूप से कमजोर हो गई है, भ्रष्टाचार आम बात हो गई है और जमीनी स्तर पर पार्टी का जुड़ाव कम हो गया है।

तराना हलीम का आरोप है कि विपक्ष की योजना हिंसा के जरिये पुलिस और सुरक्षा बलों को हतोत्साहित करने और फिर सार्वजनिक परिवहन एवं यात्रियों पर हमला करके आम लोगों को आतंकित करने की है। वह कहती हैं कि उनकी सरकार को दोतरफा हमले का सामना करना पड़ रहा है-एक, अमेरिका द्वारा संचालित पश्चिमी शासन परिवर्तन ऑपरेशन और दूसरा, लोकतांत्रिक आंदोलन के मुखौटे के पीछे योजनाबद्ध हिंसा के जरिये सरकार को हटाने के लिए पाकिस्तान के समर्थन से चलने वाला हिंसक विपक्षी आंदोलन।

अमेरिका ने दिसंबर, 2021 में पूर्व पुलिस प्रमुख बेनजीर अहमद सहित सात वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध जारी किए और बांग्लादेश को अपने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन से भी बाहर रखा। बेनु घोष का कहना है कि बीएनपी-जमात गठबंधन ने सत्ता हासिल करने की लड़ाई को लोकतंत्र बचाने की लड़ाई की तरह दिखाने के लिए अमेरिका में राजनीतिक रूप से अच्छे संपर्क वाले लॉबिस्टों को काम पर लगाया है। लेकिन बीएनपी के अब्बास ने, जिन्हें %हिंसा भड़काने% के आरोप में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ हिरासत में लिया गया, जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने आंदोलन के बाद भय का माहौल बनाने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया है, जिसका उद्देश्य चुनाव में धांधली के लिए अभी से मंच तैयार करना है।

अब्बास ने मीडियाकर्मियों को बताया कि हसीना निष्पक्ष चुनाव नहीं जीत सकतीं। अगर तटस्थ कार्यवाहक सरकार के अधीन चुनाव कराया जाए, तो अवामी लीग 10 फीसदी सीटें भी नहीं जीत सकतीं, क्योंकि भारी भ्रष्टाचार के कारण सत्ता विरोधी लहर मजबूत है और जरूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि से लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। यही वजह है कि वह सत्ता में वापसी के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करना चाहती हैं। लेकिन कट्टरवादियों का विरोध करने वाले धर्मनिरपेक्ष राजनेता नरम इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए अवामी लीग को दोषी मानते हैं। अवामी लीग को सहयोग करने वाली एक पार्टी के वरिष्ठ वामपंथी राजनेता ने बताया कि %यह न केवल पार्टी की धर्मनिरपेक्ष परंपराओं से विचलन है, बल्कि इससे इस्लामी कट्टरपंथियों को राजनीतिक वैधता हासिल करने में मदद मिली है।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कट्टर इस्लामवादियों और अमीर व्यावसायिक साथियों ने हसीना को घेर लिया है और एक मंडली तैयार की है। इससे एक ओर राजनीति का इस्लामीकरण हुआ, दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा। इससे भारत खुश नहीं है। नई दिल्ली ने इस्लामवादी-व्यापारी लॉबी को खत्म करने और अवामी लीग नेतृत्व को अपनी पारंपरिक बंगाली मध्यवर्ग की जड़ों में लौटने के लिए दबाव बनाया है, पर इसमें बहुत सफलता नहीं मिली है। अब जब अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर हसीना पर निशाना साध रहे हैं और चीन बांग्लादेश की घरेलू राजनीति से सख्ती से दूर रह रहा है, तब आयरन लेडी शेख हसीना को या तो नई दिल्ली की सलाह माननी होगी या फिर इसकी उदासीनता का जोखिम उठाना होगा।

हिन्द स्वराज्य

छुटकारा

प्रश्न- आपके विचारों से ऐसा लगता है कि आप एक तीसरा ही पक्ष कायम करना चाहते हैं। आप एक्स्ट्रीमिस्ट भी नहीं हैं और मॉडरेट भी नहीं हैं।

उत्तर- यहाँ आपकी भूल होती है। मेरे मन में तीसरे पक्ष का कोई खयाल नहीं है। सबके विचार एक से नहीं रहते। मॉडरेटों में भी सब एक ही विचार के हैं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिसे (लोगों की) सेवा ही करनी है उसके लिए पक्ष कैसा? मैं तो मॉडरेटों की सेवा करूँगा और एक्स्ट्रीमिस्टोंकी भी करूँगा। जहाँ उनके विचार से मेरी राय अलग पड़ेगी वहाँ मैं उन्हें नम्रता से बताऊँगा और अपना काम करता चलूँगा।

प्रश्न- अगर आप दोनों से कहना चाहें तो क्या कहेंगे?

उत्तर- एक्स्ट्रीमिस्टों से मैं कहूँगा कि आपका हिन्दुस्तान के लिए स्वराज्य हासिल करने का है। स्वराज्य आपकी कोशिश से मिलने वाला नहीं है। स्वराज्य तो सबको अपने लिए पाना चाहिए और सबको उसे अपना बनाना चाहिए। दूसरे लोग जो स्वराज्य दिला दें वह स्वराज्य नहीं है, बल्कि परराज्य है। इसलिए सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकाला कि आपने स्वराज्य पा लिया, ऐसा अगर आप मानते हों तो वह ठीक नहीं है। सच्चा स्वराज्य जो मैंने पहले बताया वही होना चाहिए। उसे आप गोला-बारूद से कभी नहीं पायेंगे। गोला-बारूद हिन्दुस्तान को सधेगा नहीं। इसलिए सत्याग्रह पर ही भरोसा रखिये। मन में ऐसा शक भी पैदा न होने दीजिये कि स्वराज्य पाने के लिए हमें गोला-बारूद की जरूरत है। मॉडरेटों से मैं कहूँगा कि हम खाली आजिजी करना चाहें, यह तो हमारी हीनता होगी। उसमें हम अपना हलकापन कबूल करते हैं। अंग्रेजों से सम्बन्ध रखना हमारे लिए जरूरी हैं, ऐसा कहना हमारे लिए ईश्वर के चोर बनने जैसा हो जाता है। हमें ईश्वर के सिवा और किसी की जरूरत है, ऐसा कहना ठीक नहीं है और साधारण विचार करनेसे भी हमें लगेगा कि अंग्रेजों के बिना आज तो हमारा काम चलेगा ही नहीं, ऐसा कहना अंग्रेज को अभिमानी बनाने जैसा होगा। अंग्रेज बोरिया-बिस्तर बाँधकर अगर चले जायेंगे, तो हिन्दुस्तान अनाथ हो जायेगा ऐसा नहीं मानना चाहिए।

क्रमश: ...

विधानसभा चुनावों में ही लोकसभा की तैयारी कर रही कांग्रेस

विनोद अग्निहोत्री

कहावत है कि दूध से जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इस बार पांच राज्यों विशेषकर तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2019 के दूध से जली कांग्रेस अब 2024 के लिए 2023 का छाछ फूंक फूंक कर पी रही है। यानी 2018 के विधानसभा चुनावों में इन तीनों राज्यों में जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनावों में बुरी तरह हार गई थी। इसलिए इस बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में ही लोकसभा चुनावों के लिए अपनी तैयारी और प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेता अपने चुनाव प्रचार में विधानसभा चुनावों में जीत के लिए वोट मांगने के साथ ही केंद्र में अपनी सरकार बनने पर क्या काम किए जाएंगे, उन्हें भी गिनाकर लोगों को लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार कर रहे हैं। जबकि पिछली बार कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में राज्य स्तर के मुद्दों तक ही खुद को सीमित रखा था।

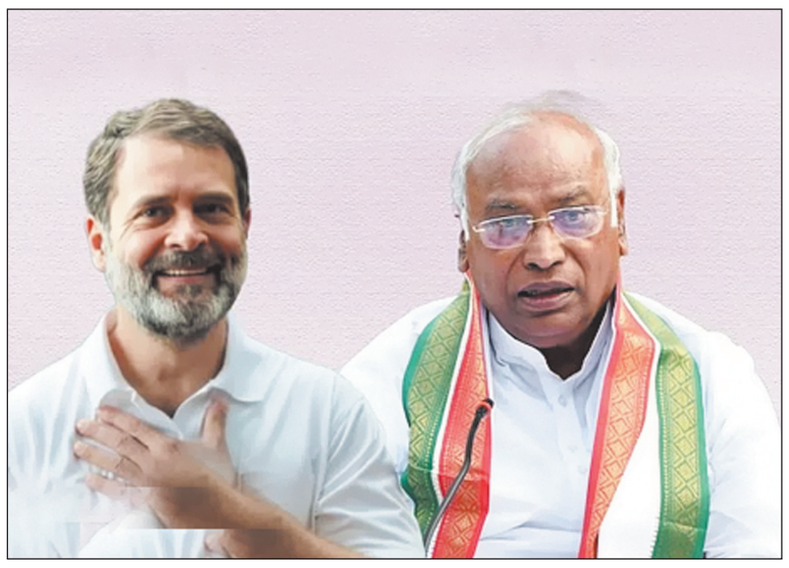

कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी पूरी तरह से चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। खरगे ने जहां दक्षिणी राज्य तेलंगाना में प्रचार की कमान संभाली है, वहीं राहुल प्रियंका ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तूफानी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी सभाओं में राहुल गांधी जहां लोगों को बता रहे हैं कि 2018 में उन्होंने प्रचार के दौरान जो वादे किये थे, वो सारे वादे राज्य की कांग्रेस सरकार ने पूरे कर दिए हैं।

राहुल कहते हैं कि वह जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं और जनता का भरोसा नहीं तोड़ते इसके साथ ही राहुल गांधी छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा करते हैं कि अगर 2024 में दिल्ली यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो धान के कटोरे के रूप में मशहूर इस राज्य को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाएंगे। इसके लिए राज्य के हर जिले में खाद्य प्रस्सकरण केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ की कृषि उपजों खासकर चावल, फल और सब्जियों के प्रतिउत्पाद तैयार होंगे और इन्हें विश्व के बाजार में भेजने के लिए राज्य में तीन चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनवाए जाएंगे। केंद्र में सरकार बनने पर राज्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हब बनेंगे और छत्तीसगढ़ के युवाओं को विश्व स्तर की कंपनियों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। राहुल कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का चावल अमेरिका जापान इंग्लैंड यूरोप और दूसरे देशों के लोग खाएंगे और कहेंगे कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया।

इसके साथ ही राहुल गांधी जातिगत जनगणना को भी विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों का मुद्दा भी अभी से बना रहे हैं। वह हर सभा में कह रहे हैं कि भारत सरकार के लगभग 40 लाख करोड़ के वार्षिक बजट का सिर्फ पांच फीसदी हिस्सा वह अधिकारी खर्च करते हैं जो पिछड़े वर्गों से आते हैं। इसी तरह दलित और आदिवासी अधिकारी भी महज तीन से चार फीसदी हिस्सा खर्च करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को चलाने वाले शीर्ष अफसरों में कैबिनेट सचिव समेत जो कुल 90 सचिव हैं उनमें सिर्फ तीन ओबीसी हैं और इसी तरह दलित और आदिवासी अधिकारियों की भी तादाद बेहद कम है। यहां भी राहुल गांधी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए जातीय जनगणना को देशव्यापी केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है।

इस तरह राहुल अपने भाषणों से विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनावों के लिए भी राज्य के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं ताकि पार्टी 2019 की तरह गफलत में न रहे। राहुल की इसी लाइन पर उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी अपनी सभाओं में बोल रही हैं। दरअसल, पांच राज्यों जहां चुनाव हो रहे हैं, उनमें तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस दोनों राज्यों के क्षेत्रीय दलों बीआरएस और एमएनएफ के मुकाबले खुद को मुख्य लड़ाई में ले आई है। उसे उम्मीद है कि इन दोनों राज्यों में वह सरकार बनाने की करीब पहुंच सकती है, जबकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसका भाजपा से सीधा मुकाबला है। यहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जीतने की पूरी उम्मीद है, जबकि राजस्थान में बकौल राहुल गांधी कांग्रेस का भाजपा से कड़ा मुकाबला है।

आम धारणा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं का फैसला आमतौर पर अलग अलग होता है। कम से कम 2004 से यह सिलसिला जारी है। जब 2003 में भाजपा ने कई विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करके लोकसभा चुनाव 2004 में समय से पहले करवा दिए, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से ही लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों के नतीजे अलग अलग आते रहे। 2018-19 इसका सबसे ताजा उदाहरण है। 2018 में उत्तर भारत के प्रमुख राज्य जीतकर कांग्रेस गफलत और गुमान में आ गई कि अब 2019 के लोकसभा चुनावों में वह अकेले भाजपा को हरा देगी, लेकिन नतीजे उलटे रहे।

इसलिए कांग्रेस इस बार पिछली गलतियों से सबक सीख कर फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। जहां 2019 में कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के लिए कोई ठोस और सार्थक पहल नहीं की थी, वहीं इस बार उसने सभी प्रमुख विपक्षी दलों को एकजुट करके इंडिया गठबंधन बनाने में कामयाबी हासिल की है। उसकी कोशिश है कि नवंबर में हो रहे इन विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा राज्य जीतकर गठबंधन में अपनी स्थिति ज्यादा प्रभावशाली बनाने के साथ ही भाजपा विरोध की धुरी भी बन जाए और इसका फायदा इस बार उसे उन राज्यों में लोकसभा चुनावों में मिले जिनमें पिछली बार उसका सफाया हो गया था।

इसीलिए इस बार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की पूरी रणनीति लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और चुनाव प्रचार में भी यह बात सामने आ रही है। कहा ये भी जा रहा है कि विधानसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ों यात्रा के दूसरे चरण के रूप में सघन जनसंपर्क के लिए निकल सकते हैं। इस बार उनका लक्ष्य उत्तर और पूर्वी भारत के राज्य होंगे जो पिछली यात्रा में छूट गए थे। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा विरोधी माहौल की धुरी राहुल गांधी को बनाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन यह सब विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता किस हद तक होगी, उस पर निर्भर करेगा।

नीतीश कुमार के आगामी उत्तर प्रदेश दौरे के मायने

ठाकुर शक्तिलोचन शांडिल्य

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तरप्रदेश का दौरा करेंगे। जदयू ने अब यूपी में पांव पसारने का मन बना लिया और संगठन अब इसकी तैयारी में जोर-शोर से लगने वाला है। उत्तर प्रदेश में जदयू का संगठन विस्तार होगा। शनिवार को उत्तर प्रदेश जदयू के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और यूपी में पार्टी के अभियान को लेकर आग्रह किए। संगठन के विस्तार को लेकर सीएम से चर्चा भी की गयी। उत्तर प्रदेश के कई जदयू नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। सीएम ने उन्हें आश्वासन दिया है कि नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में वो उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे पहले भी उत्तर प्रदेश जाते रहे हैं और बिहार में भी लगातार दौरा करते रहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री आवास में उत्तर प्रदेश के जदयू नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश में पार्टी का अभियान शुरू करने का आग्रह किया। इस दौरान संगठन विस्तार पर प्रमुखता से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उत्तर प्रदेश के करीब 65 जदयू नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक काम करने वालों ने मुलाकात की। उन सभी ने मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहले से ही समय मांगा था और मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें समय दिया गया था। इस मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में संगठन विस्तार पर चर्चा हुई। साथ ही पार्टी ने तय किया है कि बड़े स्तर पर सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री मिलने के दौरान उत्तर प्रदेश जदयू नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक काम करने वालों ने पार्टी संगठन सहित इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए मिलकर काम करने का भरोसा दिलाया। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी सियासी दलें जुट चुकी हैं। जदयू अब एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। इस बार भाजपा और जदयू अलग-अलग चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी दलें एकजुट हो रही हैं। कई सियासी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन एकजुट होकर एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं जदयू ने उत्तर प्रदेश में अब संगठन को विस्तार देने की तैयारी शुरू की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश से आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले नेताओं की यह भी इच्छा है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव भी लड़े। हालांकि यह पहली बार नहीं जब नीतीश कुमार को यूपी से चुनाव लड़ाने की चाहत यूपी के जदयू नेताओं में दिखी हो। पहले भी कई बार उनकी भावनाएं बाहर आयी हैं। खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तक इसपर बयान दे चुके हैं। ललन सिंह ने इन नेताओं की मुलाकात के बाद व पूर्व में दिए अपने बयान में कहा था कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनाव के मैदान में उम्मीदवार बनकर उतरेंगे या नहीं। लेकिन कार्यकर्ताओं की मांग है कि वो यूपी से चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार को फूलपुर, मिर्जापुर या आंबेडकर नगर से चुनाव लड़ाने की मांग कार्यकर्ता करते हैं। समय आने पर सब तय होगा। खुद सीएम ही इसपर फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश में जदयू के प्रदर्शन की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जदयू को एक बार एक सीट पर जीत मिली चुकी है। तब बीजेपी के साथ जदयू का गठबंधन था। 2009 में जदयू का खाता नहीं खुल सका जबकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू ने यूपी में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। वहीं बात विधानसभा चुनाव की करें तो 2007 में जदयू पे 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारा था। 2012 में जदयू ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और 18 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। 2017 में जब जदयू एनडीए से अलग हुआ। 2022 के चुनाव में सीट शेयरिंग पर बात भाजपा के साथ नहीं बनी थी। जदयू 20 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी जिसमें एक भी सीट पर सफलता नहीं मिली। जदयू अब यहां अपने संगठन को मजबूती देने में जुटता दिख रहा है।

राजस्थान में पानी का संकट है बड़ा चुनावी मुद्दा

विनोद पाठक

राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक मल्टी स्टोरी सोसाइटी में ट्यूबवेल सूख चुके हैं। 400 से अधिक परिवार पानी के टैंकरों के भरोसे चल रहे हैं। यह स्थिति केवल एक सोसायटी तक सीमित नहीं है। राज्यभर में कई रेजिडेंशियल इमारतों में यही हालात हैं। यही स्थिति किसानों की भी है। पानी नहीं होने के कारण फसलें सूख जाती हैं। राज्य में चंद दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन पानी के मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों में गंभीरता कम नजर आ रही है। नेता केवल बयानबाजी अधिक कर रहे हैं, जबकि ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी), जवाई बांध, पंजाब से गंगनहर में पानी छोड़ने और बीसलपुर बांध से किसानों को पानी न मिलने को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। वहीं, शहरों में पानी का मुद्दा किसी खास चर्चा में नहीं है। राजस्थान का जिक्र आते ही सबसे पहले पानी की कमी का ख्याल आता है। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जिले तो देश के सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त हैं और यहां बेहद कम बारिश होती है। वर्तमान में कुछ-कुछ यही स्थिति पूर्वी राजस्थान में भी है। केवल हाड़ौती ही ऐसा क्षेत्र है, जहां पानी की समस्या थोड़ी कम है। सबसे पहले ईआरसीपी की बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट को तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार ने बनाने का वादा किया था। प्रोजेक्ट से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, अजमेर, बूंदी, झालावाड़, कोटा व बारां की पेयजल और सिंचाई की जरूरतें पूरी होंगी। हालांकि, वर्ष 2018 के दिसंबर में वसुंधरा सरकार सत्ता से बाहर हो गई। कुछ दिनों तक यह मुद्दा लटका रहा, लेकिन वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने की मांग करते हुए हवा दे दी। मुख्यमंत्री का कहना था- जयपुर और अजमेर की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे, लेकिन अब वो अपनी बात से मुकर रहे हैं। पिछले दो-तीन साल से ईआरसीपी भाजपा और कांग्रेस के बीच में वाद-विवाद का बड़ा कारण बना हुआ है। हालांकि, जोधपुर सांसद और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो मुख्यमंत्री गहलोत के बड़े प्रतिद्वंद्वी हैं, का स्पष्ट कहना है- ईआरसीपी की डीपीआर में खामियां हैं और इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं दिया जा सकता। मुख्यमंत्री समस्या के समाधान के बजाय इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। शेखावत ने पिछले दिनों इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी राजस्थान का दौरा भी किया था। कारण, वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान के जिलों में भाजपा को भारी नुकसान हुआ था और पार्टी इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। कांग्रेस ईआरसीपी के बहाने इन 13 जिलों में चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए प्रयासरत है। पिछले दिनों ईआरसीपी को लेकर बारां से कांग्रेस ने एक यात्रा भी निकाली।

अखिलेश की साइकिल यात्रा से कांग्रेस को बड़ा संदेश!

आशीष तिवारी

आने वाले चुनावों में जिन समुदायों को साध कर कांग्रेस अपनी सियासी नींव मजबूत करना चाह रही है, उन्हीं समुदायों पर समाजवादी पार्टी लगातार अपनी दावेदारी ठोक रही है। बीते कुछ दिनों में जिस तरह से कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय के नेताओं को अपने साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू किया, वह उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर केंद्र की राजनीति को एक संदेश देने की कोशिश है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में बड़ा संदेश देने की तैयारी में आगे बढ़ रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश की पीडीए यात्रा वैसे तो सत्ता पक्ष के खिलाफ और अपनी पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए चल रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से जिस तरह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में तनाव बढ़ा है, उससे इस यात्रा के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं।

वैसे तो अखिलेश की पीडीए यात्रा बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं के मुताबिक पार्टी की यह यात्रा उनके चुनावी एजेंडे और उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा के चुनावों की मजबूती के लिहाज से शुरू की गई है। लेकिन राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी ने एक साथ कई संदेश दे दिए हैं। इन संदेशों में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शामिल है, बल्कि इ्रहष्ठद्ब गठबंधन की अहम साझेदार पार्टी कांग्रेस के लिए भी इस यात्रा के माध्यम से बड़े सियासी संदेश निकल रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक ओपी तंवर कहते हैं कि बीते कुछ दिनों में अगर उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत करीब से समझा जाए, तो समाजवादी

पार्टी और कांग्रेस के बीच में खुले तौर पर नेताओं के बीच में आमना सामना हो रहा है। शुरुआत आजमगढ़ में हुए चुनावों के नतीजे के साथ हुई। तंवर कहते हैं उसके बाद रही सही कसर मध्यप्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से गठबंधन के चलते मांगी गई सीटों के बाद पूरी हो गई।

सियासी जानकार बताते हैं कि कांग्रेस भी लगातार समाजवादी पार्टी के इस गढ़ में सेंधमारी करने की तैयारी कर रही है, जो उसका कोर वोट बैंक है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो भी वोट बैंक जुड़ा है, वह कभी कांग्रेस का ही वोट होता था। इसलिए कांग्रेस मुसलमानों से लेकर दलित और पिछड़ों की सियासत में आगे बढ़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार सदानंद तिवारी कहते हैं कि अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के माध्यम से न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत बल्कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में अपनी मजबूत राजनीतिक नींव रख रहे हैं। उनका कहना है कि गठबंधन के बावजूद भी दोनों दलों के बड़े नेताओं को छोड़ दिया जाए, तो निचले स्तर पर जमकर तनातनी चल रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा उसी राह पर चल रही है, जिस पर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने की तैयारी कर रही है।

दरअसल बीते कुछ दिनों में जिस तरह से आजम खान के मामले में कांग्रेस ने बढ़-चढ़कर बयानबाजी करनी शुरू की और उनसे मिलने की योजनाएं बनाई, वह समाजवादी पार्टी के नेताओं को रास नहीं आई। सियासी जानकारों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के इस दांव को सियासी चाल बता रहे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा में जिन बिंदुओं को शामिल कर आगे बढ़ाया जा रहा है, उसमें आजम खान का भी मुद्दा शामिल है। राजनीतिक जानकार ओपी तंवर का कहना है कि कांग्रेस ने पश्चिम में मुस्लिम नेताओं पर दांव लगाकर उनका अपने साथ जोड़ने की कवायत शुरू की है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम नेता बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में आते हैं। इससे भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में अंदरूनी तौर पर तकरार बढ़ी है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव की पीडीए यात्रा का जितना संदेश भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, उतना ही संदेश या उससे ज्यादा कांग्रेस के लिए है। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि देश में लोगों को बांटने की राजनीति करने वालों के खिलाफ यह यात्रा एक बड़े संदेश के तौर पर निकल रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस लिहाज से तो यह यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ ही है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे कांग्रेस की ओर से तैयार किए जाने वाले नए सियासी समीकरण के मद्देनजर भी देखा जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा के दौरान ही कांग्रेस पिछड़े वर्ग को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 31 अक्तूबर को कांग्रेस सरदार पटेल की जयंती पर बड़ा आयोजन कर रही है। राजनीतिक जानकारी का कहना है समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा और कांग्रेस का पिछड़े वर्ग के लिए किया जाने वाला यह सम्मेलन बताता है कि किस तरह दोनों दल आने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारी में लगे हैं।

चेहरों की राजनीति में निखरते-बिखरते चेहरे!

निरंजन परिहार

राजस्थान की राजनीति में चेहरों की जंग है। कहीं पर चेहरे की जगह कमल खिल रहा है, तो कुछ के चेहरे का रंग बदरंग है। किसी के चेहरे पर हवाईयां उड़ रही हैं, तो कोई अपना सा चेहरा लिए घूमने को मजबूर है। कुछ चेहरों पर कालिख पुत रही है, तो कोई चेहरा दमक रहा है, कोई चमक रहा है और कोई गुलाबी से काला पड़ता जा रहा है। सुर्ख चेहरों की लाली का नूर फीका पड़ रहा है और फीके चेहरों पर मीठी मुस्कान बिखर रही है। ये चेहरे कुछ कांग्रेस के मंत्रियों, विधायकों और नेताओं के हैं, तो कुछ बीजेपी के भी बड़े चेहरे हैं।

बीजेपी में वसुंधरा राजे इस चुनाव में साफ तौर पर सामने नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही कह दिया हो कि इस चुनाव में कमल ही चेहरा है। लेकिन वास्तव में देखें, तो चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही हैं, कमल तो केवल प्रतीक है। वोट कमल को नहीं, मोदी को मिलते हैं। चेहरा अगर महारानी के नाम से मशहूर वसुंधरा राजे का होता, तो लोग पसंद भी करते, क्योंकि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी के बजाय महारानी ही खिलता हुआ चेहरा है, कमल की तरह। जनता मोदी को राजस्थान का चेहरा नहीं, देश का चेहरा मानती है। प्रदेश की जनता में अपनी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम सबसे ऊपर होने के बावजूद उनके बिना कमल खिलाने की मोदी की कोशिश कितनी सफल होती है, इस पर सबकी नजर है।

हालांकि विपक्ष के नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ की उम्र 68 की होने के बावजूद उनके चेहरे पर नूर चमक रहा है तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के चेहरे की लाली भी निखर रही है। इनके उलट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और देवजी पटेल के चेहरों का रंग उड़ा हुआ है। दोनों सांसदों को विधानसभा की उम्मीदवारी दिये जाने के बाद से उनके इलाके में ही दोनों का जबरदस्त विरोध हो रहा है।

तीन बार के सांसद देवजी पटेल को उनके गृह नगर सांचोर से विधानसभा का उम्मीदवार बनाते ही उनके खिलाफ विरोध का फव्वारा फट पड़ा है। उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा धक्का मुक्की से लेकर उनकी गाड़ी के कांच तक फोड़े गए हैं। सांचोर में जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी सहज उम्मीदवार थे, लेकिन देवजी ने पार्टी की उम्मीदवारी स्वीकारी तो विरोध तो होना ही था। अब देवजी की जीत पर खतरा मंडरा रहा है।

उधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को झोटवाड़ा से उम्मीदवार बनाया गया, तो पहले से ही वहां के दमदार नेता तथा पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत के समर्थकों ने %कर्नल कहना मान ले, बोरियां बिस्तर बांध ले के नारों से विरोध शुरू कर दिया है। कल तक राज्यवर्धन के भी कार्यकर्ता ये ही थे, लेकिन उम्मीदवारी मिलने के बाद राज्यवर्धन स्वयं जब उनको प्रसाद स्वरूप लड्डू खिलाने गए, तो भी उन्होंने विरोध किया और प्रेम से गले लगाने निकले, तो उनसे मिलना तक गवारा नहीं समझा।

इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के चेहरे की लाली बढ़ रही है। उनको भरोसा है कि सरकार उनकी ही आनी है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो जीत का श्रेय भी उन्हीं को मिलना है। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जोशी का सारे बड़े नेताओं से संबंध बढ़ता जा रहा है और यही नूर उनके चेहरे पर निखार भी ला रहा है।

कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इस चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़े नेता के रूप में सबके सामने हैं। गहलोत की राजस्थान के मुखिया के नाते शुरू की गई योजनाओं की हर तरफ प्रशंसा हो रही है, तो निश्चित रूप से चेहरा तो उन्हीं को होना था। बीजेपी में नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी को राजस्थान में पार्टी का चेहरा बनाने का रिस्क कांग्रेस नहीं ले सकती। चेहरा तो सचिन पायलट भी अपना चमकाने की जुगत में बीते तीन महीने से विरोध के स्वर सहेजकर शांति धारण किए हुए हैं और अपनी लुभावनी अंग्रेजी से आलाकमान को पटाने में लगे हैं। लेकिन गहलोत को देखते ही या उनका नाम सुनते ही पायलट के चेहरे का रंग बदरंग हो जाता है।

तीन बार सांसद, केंद्र में मंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद किसी धुरंधर राजनेता की तरह पायलट अपने चेहरे के भाव छुपा नहीं पाते, इसे उनकी कमजोरी माना जाता है। चेहरा कांग्रेस सरकार के वरिष्ठ मंत्री महेश जोशी का भी उतरा हुआ है। नई दिल्ली में 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में टिकट पाने की ललक में उनको अकेले और लगभग अनाथ की तरह घूमते देख कईयों को उन पर तरस आ रहा था। महेश जोशी मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी मंत्री हैं और 25 सितंबर 2022 को आलाकमान को आंख दिखाने की विधायकों की कोशिश का करतब उन्हीं के खाते में दर्ज किया गया है।

कांग्रेस सरकार के कुछ और चेहरों की बात की जाए, तो शांति धारीवाल के चेहरे पर कोटा में रिवर फ्रंट बनाने में करोड़ो की कमाई के दाग है, प्रतापसिंह खाचरियावास की कैंची की तरह चलती जुबान का जिक्र तो खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के भाषण सुनने वाले उनकी लुभावनी और ठेट देसी शब्दावली के कायल हैं, मगर उनके चुनाव क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में उनके सामने बीजेपी के दमदार उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया के होने से हार का डर अभी से मंडराने लगा है। उधर, चुनाव से पहले गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस का जो गुलाबी नजारा गली गली गुल खिला रहा था, वह बीजेपी की दमदार कोशिशों के कारण क्या आकार ले रहा है, यह सभी को दिख रहा है।

राजस्थान की राजनीति के चेहरों के बदरंग होते रंग और फीके पड़ते नूर का यह सिलसिला अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और जीतने हारने तक लगातार आगे बढ़ते रहेगा। फिर उसके बाद अगली सरकार बनने तक कोई हंसेगा, तो नई सरकार बनने के बाद पिछली सरकार का कोई फंसेगा। लेकिन फिलहाल निखरते - बिखरते राजस्थान के ये सभी बड़े चेहरे हैं। सारे के सारे धुरंधर, सारे के सारे मंजे हुए और अपने अपने इलाकों में मजबूत भी। मगर, किसी नेता को अहंकार भारी पड़ा, तो किसी को उसका व्यवहार। किसी पर उसकी हरकतें बदनुमा दाग बनकर उभरीं, तो कोई अथाह कमाई के फेर में फंस गया। ये सभी प्रदेश की राजनीति की धुरी माने जाते हैं। लेकिन धुरी ही जब ढीली पड़ जाए, तो राजनीति के रंग अपने रंग दिखाते ही हैं।

इसी वजह से राजस्थान में विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले जो गुलाबी परिदृश्य प्रतिबिंबित हो रहा था, उसकी तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है और नेताओं के चेहरों के हाव भाव भी बदल रहे हैं। लेकिन नहीं बदल रही है, तो वह है राजनीति की रंगत, जो इस चुनाव में कुछ ज्यादा ही निखर रही है।

करवा चौथ और संकष्टी चतुर्थी का व्रत

पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस पर्व में चंद्रमा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएं दिनभर निर्जला उपवास रखकर शाम को चंद्रमा निकलने के बाद ही अपना उपवास खोलती है।

ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि, इस साल करवा चौथ सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग में मनाई जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस साल करवा चौथ के दिन ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। कृष्णपक्ष की चतुर्थी के दिन यह व्रत किया जाता है और इस साल यह तिथि बुधवार 1 नवंबर को है। बुधवार 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का योग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 06:33 मिनट से 2 नवंबर को सुबह 04:36 मिनट रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 02:07 मिनट से शिवयोग शुरू हो जाएगा।

सबसे खास बात यह है कि इस साल करवा चौथ के दिन ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाएगा। जोकि करवा चौथ के महत्व और भी ज्यादा बढ़ा देता है। यानी इस साल करवा चौथ के दिन जो भी व्रत रखकर पूजा अर्चना करेगा। उनको भगवान शिव और गणेशजी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा।ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वहीं इस साल चतुर्थी तिथि 31 अक्टूबर की रात 9:30 मिनट से शुरू हो रही है। जिसका समापन अगले दिन यानी 1 नवंबर की रात 09:19 मिनट पर होगा। उदयातिथि के अनुसार 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। 1 नवंबर को पति-पत्नी का महापर्व करवा चौथ है। ये व्रत जीवनसाथी के लिए समर्पण, प्रेम और त्याग का भाव दिखाता है।

महिलाएं पति के सुखी जीवन, सौभाग्य, अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए दिनभर निराहार और

निर्जल रहती हैं। इस रिश्ते में जब तक एक-दूसरे के बीच विश्वास है, तब तक प्रेम बना रहता है। अगर जीवन साथी पर अविश्वास का भाव जाग जाता है तो ये रिश्ता टिक नहीं पाता है।

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से चंद्रोदय तक रखे जाने वाले इस व्रत को महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। करवा चौथ व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और पति की आयु लंबी होती है। इसलिए विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं।

इस दिन चंद्रमा के साथ-साथ शिव-पार्वती सहित गणेशजी व मंगल ग्रह के स्वामी देव सेनापति कार्तिकेय की भी विशेष पूजा होती है। करवा चौथ से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं, जो इसे और खास बनाती हैं। करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और राजस्थान आदि राज्यों में मनाया जाता है। माना जाता है कि, ये व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में भी सुख बना रहता है।

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत मंगलवार 31 अक्टूबर को रात 9:30 मिनट से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 मिनट तक रहेगी। ऐसे में उदयातिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत बुधवार 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा।

करवा चौथ पर बन रहा शुभ संयोग

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 06:33 मिनट से 2 नवंबर को सुबह 04:36 मिनट रहेगा। इसके अलावा 1 नवंबर की दोपहर 02:07 मिनट से शिवयोग शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और बढ़ गया है।

करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर

-चतुर्थी तिथि आरंभ: 31 अक्टूबर को रात 9:30 मिनट से

-चतुर्थी तिथि समाप्त: 1 नवंबर की रात 09:19 मिनट पर

चंद्र दर्शन का समय

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि वहीं ये भी मान्यता है कि कि ऐसे समय में चंद्र दर्शन मनवांछित फल प्रदान करता है। 1 नवंबर 2023 यानी करवा चौथ की रात्रि 08:15 बजे चंद्रोदय होगा।

करवा चौथ पूजा शुभ मुहूर्त

-1 नवंबर को सायं 05:36 मिनट से 06:54 मिनट तक

-अमृतकाल मुहूर्त- सायं 07:34 मिनट से 09:13 मिनट तक

-इस समय आप चंद्रमा को देखकर व्रत का पारण सकते हैं। यह समय काफी शुभ रहने वाला है।

पति के लिए व्रत की परंपरा

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने की परंपरा सतयुग से चली आ रही है। इसकी शुरुआत सावित्री के पतिव्रता धर्म से हुई। जब यम आए तो सावित्रि ने अपने पति को ले जाने से रोक दिया और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा से पति को फिर से पा लिया। तब से पति की लंबी उम्र के लिए व्रत किए जाने लगे। दूसरी कहानी पांडवों की पत्नी द्रौपदी की है। वनवास काल में अर्जुन तपस्या करने नीलगिरि के पर्वत पर चले गए थे। द्रौपदी ने अुर्जन की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण से मदद मांगी। उन्होंने द्रौपदी को वैसा ही उपवास रखने को कहा जैसा माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। द्रौपदी ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय के पश्चात अर्जुन वापस सुरक्षित लौट आए।

चांद निकलने तक रहता है व्रत

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाने की परंपरा है। पति की लंबी उम्र की कामना से महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं। यानी पूरे दिन पानी भी नहीं पीती। सुहागिनों के लिए ये व्रत बहुत खास होता है। इसका इंतजार महिलाओं को साल भर रहता है।

करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से शुरू होता है और शाम को चांद निकलने तक रखा जाता है। शाम को चंद्रमा के दर्शन करके अर्घ्य अर्पित करने के बाद पति के हाथ से पानी पीकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। इस दिन चतुर्थी माता और गणेशजी की भी पूजा की जाती है।

करवा चौथ पर सुहागिने न करें ये गलती

करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को सफेद और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ऐसा माना जाता है करवा चौथ के दिन इस रंग के कपड़े पहनना अशुभ होता है।

करवा चौथ के दिन कोशिश करें लाल और गुलाबी के रंग वस्त्र पहने, ये रंग सुहाग का प्रतीक होते हैं।

करवा चौथ के दिन महिलाओं को तेज धार वाली चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए जैसे सुई, चाकू आदि, करवा चौथ के दिन कटना और चोट लगना अशुभ माना जाता है।

करवा चौथ के दिन बड़ों का अपमान बिलकुल ना करें, बड़ों से बहस या लड़ाई झगड़ नहीं करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें।

करवा चौथ के अच्छे से सोलाह शृंगार करें, इस दिन सजना संवरना शुभता का प्रतीक माना गया है।

करवा चौथ के दिन शृंगार का सामान दान ना करें, इस दिन शृंगार का सामान दान करना अशुभ होता है। इसीलिए ऐसा करने से बचना चाहिए।

शादी के बाद पहली बार रख रही हैं करवाचौथ का व्रत तो रखें इन बातों का ख्याल

करवाचौथ का व्रत का बहुत महत्व हैं। लेकिन अगर आप नवविवाहिता है और आपकी नई-नई शादी हुई है और ये शादी के बाद आपका पहला करवाचौथ का व्रत को इन बातों को जान लें और ध्यान में जरूर रखें।

जरुर करें 16 शृंगार

शादी के बाद अगर आप पहली बार करवाचौथ का व्रत रख रही हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि 16 शृंगार करके ही इस दिन रहें। ये दिन महिलाओं के लिए सुहाग का दिन हैं, सुहाग शृंगार का गहरा संबंध है।

मेंहदी लगाएं

इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने शृंगार में मेंहदी जरुर लगाती है। मेंहदी लगाना बेहद जरुर होता है। इस दिन हर शादीशुदा महिला के हाथ पर मेंहदी होती है।

सरगी

करवाचौथ पर सरगी का बहुत महत्व होता है। इस दिन किसी भी किमत पर सरगी खाना नहीं भूलना चाहिए। अगर आप करवाचौथ का व्रत पहली बार रख रही हैं तो इस दिन ध्यान में रखें कि सुबह जल्दी उठ कर सरगी जरुर खाए, सरगी में 7 चीजें खाने का विधान हैं।

लाल रंग का महत्व

अगर आप पहली बार करवाचौथ का व्रत रख रही हैं तो इस दिन आपको ध्यान में रखा चाहिए की लाल या लाल का रंग गुलाबी रंग ही पहने। इस रंग को पहनना शुभ माना गया है।

ना पहने इस रंग के कपड़े

अगर आप पहली बार करवाचौथ का व्रत रख रही हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि काला, नीले, भूरे या सफेद रंग के कपड़े बिलकुल भू ना पहने। इस रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है।

व्रत पारण नियम

करवाचौख में व्रत पारण चांद को अर्घ्य देकर ही करना चाहिए। व्रत के बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। इस दिन व्रत के बाद मांस का सेवन ना करें। केवल शुद्ध खाना ही खांए।

आशीर्वाद जरुर लें

अगर आप पहली बार करवाचौथ का व्रत रख रही हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सुबह अपने बड़ों का आशीर्वाद जरुर लें, साथ ही शाम को करवाचौथ की पूजा के बाद भी बड़ों का आशीर्वाद जरुर लेना चाहिए।

ऐसी मान्याता है अगर आप करवाचौथ के दिन विधि विधान के साथ करवाचौथ का व्रत रखती हैं तो आप अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है।

कैसे सजाएं करवा चौथ की थाली

करवा चौथ की थाली करवा चौथ की पूजा में एक प्रमुख साम्रगी होती है। हर सुहागिन बड़े ही चाह से इसको खरीदती है और इसको सजाती है। करवा चौथ की थाली में क्या-क्या होना चाहिए आइये जानते हैं।

-करवा चौथ की थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए, उस दीपक में रुई की बात्ती का होना जरुरी है।

-मिट्टी का करवा पूजा की थाली में होना चाहिए।

-एक जल का कलश होना बहुत जरुरी है जिससे आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे।

-छलनी का होना भी जरुरी है, जिससे आप चांद के दर्शन करें।

-पानी का गिलास पूजा की थाली में होना बहुत जरुरी है, जिस लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ्य दे उस लोटे से पानी ना पीए, बल्कि पानी गिलास से ही पीए।-फूल, चावल, मिठाई, घी, रोली, कुमकुम, इन सभी चीजों का होना करवा चौथ की थाली में अनिवार्य है। चंद्र देव के दर्शन के बाद उनकी सबसे पहने पूजा करें, उनको रोली, कुमकुम, अक्षत चढ़ाए, उनकी आरती उतारे, मिठाई का भोग लगाएं, उसके बाद अपने पति की पूजा करें।

कार्तिक मास के पांच नियम

धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वह वर्ष भर स्वास्थ्य सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान-दान, व्रत-उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का माहात्म्य सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का शमन होता है।

यूं तो कार्तिक मास में अनेक नियम, संयम का पालन करने का विधान है किन्तु कार्तिक मास में अगर प्रमुख पांच नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक-परलोक दोनों संवर जाता है।

पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीप-दान देना, ये कार्तिक मास के पांच प्रमुख नियम हैं।

हरिजागरणं प्रातःस्नानं तुलसिसेवनम्।
उद्यापनं दीपदानं व्रतान्येतानि कार्तिके।।

इन पांचों नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाले को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। वह फल इस लोक में ऐश्वर्य एवं परलोक में सद्गति देने वाला बताया गया है। इस मास की महत्ता स्वयं बह्माजी ने नारद जी को बताई है, ङ्यह मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्यप्रदाता, पापनाशक तथा मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है क्योंकि इस मास में सभी देव, मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं, जो इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य फल प्रदान करते हैं। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है।

कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाशदीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व से ही धन सम्पदा की देवी मां लक्ष्मी का आवाह्न करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा-अर्चना करती हैं, घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करते हैं। कार्तिक मास आरंभ होने के साथ ही प्रारम्भ हो जाता है, सूर्य तनया भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णुप्रिया तुलसी का पूजन।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला हो जाता है, नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोगजन्य स्थिति में न पहुंचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान बनाया है। कार्तिक मास में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर्ष लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु शुरू हो जाती है इसलिए कार्तिक स्नान पूजा-अर्चना मनुष्य की काम, क्रोध आदि की बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना शास्त्रों में वर्णित है।

पृथ्वी पर सूर्य किरणों की तपिश क्षीण होने के साथ ही चन्द्रमा का महत्व कार्तिक मास आरम्भ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से ही बढ़ जाता है।

कार्तिक मास में व्रत-उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ-साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अतिप्रिय है इसलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विशेष पुण्यबल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्रअर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति प्राप्त करता है।

इंसान अपना भाग्य खुद लिख सकता है

ग्रह-नक्षत्र और भाग्य के बारे में अनेक धारणा एवं मान्यता प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि भाग्य ईश्वर के द्वारा रचित है, तो कुछ लोग मानते हैं कि ग्रह-नक्षत्र हमारा भाग्य तय करते हैं तो कुछ कहते हैं कि भाग्य हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर बनता है। मनुष्य शुभाशुभ कर्म करता है, ईश्वर मनुष्य को उसके कर्मानुसार फल देता है और ग्रह-नक्षत्र कर्मफल की सूचना देने के माध्यम हैं।

कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य

मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, ज्योतिष विद्या की गणनाऐं व्यक्ति के भाग्य और सुख-दुख के बारे में सूचना देती हैं। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है, उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर-सवेर प्राप्त होता है, यानी कि, किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है, इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75000 रूपए खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75000 रूपए आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना

आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा-थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्यफल बनने के लिए कभी-कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है, यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ-अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है, हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है, इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि,

इंसान बंधा खुद लेख से
अपने, लेख विधाता, कलम से हो
कलम चले खुद करम पे
अपने, झगडा अकल ना किस्मत हो।

प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है, और किस्मत की कलम, विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा, न तो किस्मत का है और न ही अक्ल (बुद्धि) का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है, पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले-जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरुप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में दान-पुण्य, उपाय, ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपायों द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर दिया जाए तो शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकराकर निष्फल हो जाती हैं। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है, बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंक से राजा बन सकता है और एक अज्ञानी को महाज्ञानी इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करें और सही दिशा में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करें, निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन को निश्चित रूप से बदला जा सकता है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पटेल के अविस्मरणीय योगदान के कारण आज देश एकजुट है

नईदिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल के अविस्मरणीय योगदान के कारण ही आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश एकजुट है। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की 148वीं जयंती पर यहां आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने सभी नागरिकों से 2047 तक देश को सभी क्षेत्रों में दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने का संकल्प लेने को कहा। 2047 में देश अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा। उन्होंने कहा, ''आज का भारत सरदार पटेल के कारण ही संभव हो पाया है। उनके अविस्मरणीय योगदान के कारण देश आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकजुट है। सरदार पटेल के योगदान और दूरदर्शिता के बिना आज हम यहां नहीं होते।'' इस अवसर पर शाह ने 'रन फॉर यूनिटी' को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिसकी शुरुआत राष्ट्रीय राजधानी में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से हुई।

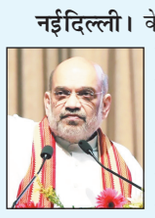

केजरीवाल को समन के बाद पंजाब तक पहुंची ईडी

नईदिल्ली। जांच एजेंसी ने ड्रग्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को ड्रग्स से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें आप विधायक कुलवंत सिंह के परिसर भी शामिल थे। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ-साथ संघीय जांच एजेंसी द्वारा मोहाली, अमृतसर और लुधियाना में स्थानों को कवर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एसएएस नगर से आम आदमी पार्टी (आप) के 61 वर्षीय विधायक कुलवंत सिंह से जुड़े मोहाली स्थित परिसर को भी कवर किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की जा रही है और समझा जाता है कि यह मादक पदार्थों और नशीली दवाओं की तस्करी के मामले से संबंधित पंजाब पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है।

आशंका है ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी : आतिशी

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को दावा किया कि ऐसी आशंका है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करने के बाद दो नवंबर को उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उसके शीर्ष नेताओं को जेल में डालकर पार्टी को खत्म करने का प्रयास कर रही है। केजरीवाल को धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत समन जारी किए गए हैं और सूत्रों के अनुसार ईडी दो नवंबर को सुबह 11 बजे केजरीवाल के जांच एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने के बाद उनका बयान दर्ज करेगी। यह पहली बार है जब ईडी ने केजरीवाल को समन भेजा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अप्रैल में इस मामले में उनसे पूछताछ की थी।

शराब घोटाले के मुख्य सूत्रधार के जेल जाने की बारी आई : भाजपा

नईदिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है जिसके बाद स्थानीय राजनीति गर्मा गयी है। इस बीच मंगलवार सुबह दिल्ली शराब घोटाला मामले में पंजाब के आप विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी की छापेमारी हो जाने से पंजाब की राजनीति में भी उबाल आ गया है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार दिल्ली और पंजाब में सत्तारुढ़ पार्टी को समाप्त करने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद शराब घोटाला मामले के मुख्य सूत्रधार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बारी आ गयी है। जहां तक अरविंद केजरीवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी समन की बात है तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होने के बाद एजेंसी मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करेगी।

चंद्रबाबू नायडू को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

हैदराबाद। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने करोड़ों रुपये के कौशल विकास मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। जमानत स्वास्थ्य आधार पर दी गई थी। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को करोड़ों रुपये के कौशल विकास निगम घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर नायडू को जमानत दे दी। 18 अक्टूबर को, नायडू के परिवार के सदस्यों और टीडीपी नेताओं ने राजामहेंद्रवरम की केंद्रीय जेल में उनसे मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी भुवनेश्वरी, बेटे लोकेश और बहू ब्राह्मणी ने जेल में टीडीपी प्रमुख से मुलाकात की। उनके साथ पार्टी नेता चिनराजप्पा, राममोहन नायडू, बुचैया चौधरी, कला वेंकटराव और अन्य भी थे।

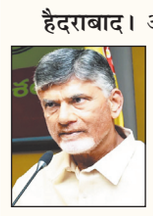

विपक्षी नेताओं को मिले अलर्ट पर बोले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष

सत्ता पीएम के नहीं, किसी और के हाथ में, हम डरने वाले नहीं : राहुल

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कई विपक्षी नेताओं ने उनके एप्पल उपकरणों की हैकिंग का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले मैं सोचता था कि नंबर 1 पीएम मोदी हैं, नंबर 2 अडानी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं, लेकिन यह गलत है। उन्होंने कहा कि नंबर 1 अडानी हैं, नंबर 2 पीएम मोदी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत की राजनीति को समझ चुके हैं और अब अडानी जी बच नहीं सकते। ध्यान भटकाने की राजनीति चल रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश की सत्ता पीएम के नहीं, किसी और के हाथ में है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि मेरे कार्यालय में कई लोगों को यह संदेश मिला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केसी वेणुगोपाल जी, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा को भी यह संदेश मिला है। भाजपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे (भाजपा) युवाओं का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आप जितनी चाहें उतनी (फोन) टैपिंग कर सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मेरा फोन लेना चाहो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि पूरे विपक्ष के खिलाफ एप्पल का नोटिस आता है। यह मेरे कार्यालय में सभी लोगों को मिला है। कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है।

राहुल ने कहा कि यह सारे किसी न किसी तरीके से इस मामले में शामिल हैं। आपका ध्यान कभी इधर, कभी उधर ले जाते हैं, आपके दिल में गुस्सा पैदा करते हैं और जब आपके अंदर नफरत आता है तब ये लोग इस देश का धन ले जाते हैं। फोन पर राज्य-प्रायोजित हमले की चेतावनी देने पर राहुल ने कहा कि यह अपराधियों और चोरों का काम है। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह दुखद बात है...मुझे सुबह यह संदेश मिला जिसमें कहा गया है कि आपका डिवाइस हैक किया जा रहा

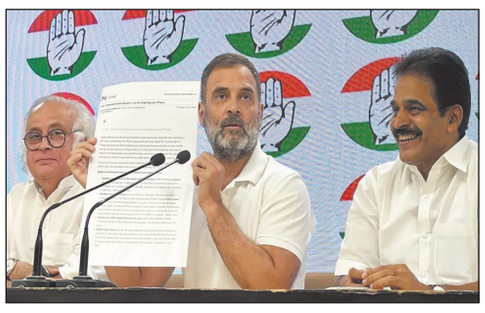

है या राज्य प्रायोजित एजेंसी द्वारा निगरानी की जा रही है... निगरानी क्यों की जा रही है? लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए।

एप्पल से आया अलर्ट, महुआ, थरूर, येचुरी और ओवैसी का दावा, क्या फोन हैक कर रही है सरकार?

टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने कई भारतीय विपक्षी नेताओं और कम से कम दो पत्रकारों को अलर्ट संदेश जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि उनके आईफ़ोन को राज्य-प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता शशि थरूर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा, कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रभारी सुप्रिया श्रीनेत और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उन्हें धमकी का नोटिफिकेशन मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) नेता सीताराम येचुरी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा को भी अलर्ट मिला।

ओवेसी को छोड़कर सभी राजनीतिक नेता भारतीय विपक्षी गुट से संबंधित हैं। ये सभी मोदी सरकार के आलोचक हैं। संदेशों ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि आपके डिवाइस से किसी राज्य-प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है, तो वे आपके संवेदनशील डेटा, संचार, या यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफ़ोन तक दूरस्थ रूप से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। अधिसूचना में कहा गया है, हालांकि यह संभव है कि यह एक गलत अलार्म है, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। इसको लेकर विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार आ गई है।

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मेरे फोन पर कल रात वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल इस्तेमाल कर रही हूं, कभी इस प्रकार का कोई मेल नहीं आया। ये एक गंभीर वार्निंग थी। उसमें साफ लिखा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स द्वारा किया गया है, ये केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित एक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि आज सुबह मुझे पता चला कि विपक्ष के कई नेताओं के पास ये मैसेज आया है। पेगासस को खारिज करने की पूरी कोशिश की गई। अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हुई, उनको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। सांसद मनोज झा ने कहा, सरकार कहे कि ये अलर्ट गलत है... ये क्या हो रहा है? आक्रामक राजनीति के तहत डिजिटल दुनिया बना रहे हैं? आप देखना चाहते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? सरकार की ओर से सफाई आनी चाहिए, इसके लिए एक मंत्रालय भी है वे क्या कर रही है?

सीताराम येचुरी ने कहा कि मुझे कल रात एप्पल से एक ई-मेल मिला जिसमें उल्लेख किया गया था कि राज्य-प्रायोजित निगरानी की जा रही है और आपका फोन और सभी सिस्टम हैक किए जा रहे हैं और इससे निपटना मुश्किल है... गोपनीयता का अधिकार है हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक को...केंद्र को इस पर स्पष्टीकरण देने की जरूरत है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह गंभीर मामला है। केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

मोदी सरकार पर विपक्ष ने लगाया फोन हैकिंग का आरोप

भाजपा ने कहा-क्या सरकार के पास कोई और काम नहीं है

नईदिल्ली। विपक्ष के कई राजनीतिक नेताओं द्वारा फोन हैकिंग के आरोप पर आक्रामक रूख अख्तियार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बेहद तीखा पलटवार किया है और विरोधी नेताओं के सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। इस संबंध में भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिन कोहली ने कहा, विपक्ष द्वारा केंद्र पर उनके फोन हैक किए जाने का आरोप बेहद हास्यास्पद है, भला हम कैसे मान लें कि भारत सरकार ने ऐसा किया है? मीडिया से बात करते हुए नलिन कोहली ने कहा, महुआ मोइत्रा के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं। इसके लिए उन्हें संसद की आचार समिति के सामने पेश होना है। उन्हें जवाब देना है कि क्या उनके ईमेल पते का इस्तेमाल एक व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने और दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था?

उन्होंने आगे कहा, महुआ पर लगे आरोप बेहद संगीन हैं और अब वो उल्टे फोन हैकिंग की बात कर रही हैं। अगर कोई हैक करने की कोशिश करता है तो फोन पर तुरंत नोटिफिकेशन आ जाता है। हम कैसे मान लें कि भारत सरकार ने ऐसा किया है? आखिर वह किस आधार पर ऐसा कह रही हैं? इसके साथ ही नलिन कोहली ने कहा, यह ध्यान भटकाने की कोशिश है और बहुत ज्यादा संभव है कि उन्होंने खुद ही अपना फोन हैक करने की कोशिश की हो? नलिन कोहली के अलावा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा के फोन हैक होने के दावे पर कहा कि अगर ऐसा उन्हें लगता है तो वह अपना मोबाइल फोन जांच के लिए दिल्ली पुलिस को दें।

भाजपा सांसद दुबे ने कहा, क्या अब भारत सरकार के पास कोई काम नहीं बचा है? चंद रुपयों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखने के आरोपी सांसद का यह घड़ियाली आंसू सच में हंसाता है। दिल्ली पुलिस को तुरंत माननीय सांसद महोदया का मोबाइल फोन लेकर जांच करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, सांसद महुआ मोइत्रा को तो तुरंत निजता के उल्लंघन का मामला दर्ज करना चाहिए न कि राहुल गांधी की तरह आरोप लगाकर भागना नहीं चाहिए। उन्होंने मोबाइल टेप के बारे में भी बात की लेकिन फोन नहीं दिया।

मालूम हो कि महुआ मोइत्रा ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई अन्य नेताओं और सांसदों ने आरोप लगाया है कि उनके ऐप्पल डिवाइस कथित हैकिंग का शिकार हुए हैं। इन नेताओं ने अपने-अपने उपकरणों पर प्राप्त चेतावनी का स्क्रीनशॉट भी सोशल प्लेटफॉर्म पर साझा किया है।

आप सांसद राघव चड्ढा का दावा है कि उन्हें भी अपने फोन पर कथित हैकिंग की सूचना मिली। सांसद चड्ढा का आरोप है कि किया कि यह सरकार का विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला है।

उन्होंने कहा, आज सुबह-सुबह मुझ एप्पल फोन से संबंधित एक अधिसूचना मिली, जिसमें मुझे मेरे फोन पर संभावित सरकार -प्रायोजित स्पाइवेयर हमले के बारे में चेतावनी दी गई थी। ये हमला मुझ पर अकेले नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं पर भी हुई है। इसलिए हर भारतीय को चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि आज यहां मैं हूं, कल यहां आप भी हो सकते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

सेमीफाइनल गणित को श्रीलंका की हार ने उलझाया

नई दिल्ली। विश्वकप 2023 में भारत अभी तक अपने सभी मैच में जीतने के साथ टॉप पर है। लेकिन, मोड़ यहां पर आ गया है कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी जगह कौन बनाएगा? इसे लेकर अभी पशोपेश की स्थिति बनी हुई है क्योंकि प्वाइंट्स टेबल में आखिर पोजिशन पर होने के बावजूद भी इंग्लैंड और बांग्लादेश अपनी दावेदारी पेश कर रही है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका और पाकिस्तान अभी की अपनी मौजूदा स्थिति के हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी में भाग ले सकती हैं।

विश्व कप 2023 में दो-तिहाई मैच हो जाने के बाद अब रेस 10 में से टॉप 4 में होने जा रही है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने घोषणा की है कि इस साल चले रहे वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में शीर्ष सात टीमें 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई करेंगी। लेकिन, हैरान करने वाली बात यह है कि प्वाइंट्स टेबल में मौजूद पाकिस्तान इस लीग की मेजबान करेगी इसीलिए उसे सीधे एंट्री मिल गई है। वहीं, अभी की स्थिति यह बनी हुई है कि विश्वकप में हिस्सा लेने वाली सभी टीमें सेमीफाइनल में पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। यहां तक कि इंग्लैंड और बांग्लादेश भी छह मैचों में सिर्फ 1-1 मैच ही जीती हैं, लेकिन अपनी दावेदारी पेश करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। अभी प्वाइंट्स टेबल में भारत टॉप पर है क्योंकि उसने अभी तक अपने खेले सभी मैच जीते हैं, जिसके चलते उसकी दावेदारी सबसे मजबूत है। विश्वकप 2023 में मौजूदा चैंपियन के लिए किसी आपदा से कम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया टीम ने बांग्लादेश को हराया है और न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका से हार गई है। विश्वकप में अब अगर सेमीफाइनल में इंग्लैंड को जगह बनानी है तो टीम को अपने बचे हुए 3 मैच को जीतना होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 238 अंक फिसला तो निफ्टी 19,100 के नीचे आया

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार का कारोबारी सत्र बहुत उतार-चढ़ाव भरा रहा और बीएसई सेंसेक्स तथा निफ्टी-50 दोनों इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई। एशियाई बाजारों में कमजोरी और इस सप्ताह के अंत में अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर निर्णय के मद्देनजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों में फिसलन से बाजार में गिरावट आई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स आज 237.72 अंक या 0.37 प्रतिशत की गिरावट लेकर 63,874.93 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की तीस कंपनियों में 16 के शेयर हरे जबकि 14 कंपनियों के शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसी तरह निफ्टी-50 में भी गिरावट दर्ज की गई और यह 61.30 अंक या 0.32 फीसदी की गिरावट लेकर 19,079.60 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में टाइटन के शेयर में सबसे ज्यादा 2.47 प्रतिशत की तेजी आई।

होनासा कंज्यूमर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुला

नईदिल्ली। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर का 1,701 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) मंगलवार (31 अक्टूबर) को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। होनासा कंज्यूमर के आईपीओ में निवेशक 2 नवंबर तक पैसे लगा सकेंगे। मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी के आईपीओ में 365 करोड़ रुपये की फ्रेश इक्विटी जारी करना और 1,336 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है। ओएफएस में शेयर पेश करने वालों में प्रमोटर वरुण अलघ और गज़ल अलघ, और फायरसाइड वेंचर्स फंड, सोफिना, स्टेलारिस, कुणाल बहल, रोहित कुमार बंसल, ऋषभ हर्ष मारीवाला और अभिनेता शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जैसे निवेशक शामिल हैं। कंपनी ने अपने इश्यू के लिए प्राइस बैंड 308-324 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है।

एलएंडटी को पश्चिम एशिया में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक रुपये का मिला कॉन्ट्रैक्ट

नईदिल्ली। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को पश्चिम एशिया में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की एक बड़ी परियोजना का ठेका मिला है। कंपनी 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को 'बड़ी' (अल्ट्रा मेगा) श्रेणी में वर्गीकृत करती है। लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, '' लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के हाइड्रोकार्बन व्यवसाय (एलएंडटी एनर्जी हाइड्रोकार्बन ङ्क एलटीईएच) को पश्चिम एशिया में प्रतिष्ठित ग्राहक से एक और 'अल्ट्रा-मेगा' परियोजना के लिए आशय पत्र मिला है।'' लार्सन एंड टुब्रो 23 अरब अमेरिकी डॉलर की भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में सक्रिय है।

युद्ध और बढ़ा तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी

नई दिल्ली। विश्व बैंक ने सोमवार को बताया है कि अगर इस्त्राइल और हमास के बीच युद्ध तेज होता है, तो तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में खाने-पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट आउटलुक में पाया गया कि यदि संघर्ष नहीं बढ़ता है तो तेल की कीमतों पर प्रभाव सीमित होना चाहिए, लेकिन यदि संघर्ष बढ़ता है तो हालात बिगड़ जाएंगे। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में छोटे, मध्यम या बड़े व्यवधान की स्थिति में वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए तीन परिदृश्यों की बात कही है। विश्व बैंक का अनुमान है कि यदि संघर्ष छोटे व्यवधान परिदृश्य से नहीं बढ़ता है तो प्रभाव सीमित होना चाहिए- ऐसे में तेल की कीमतें अगले साल औसतन 81 डॉलर प्रति बैरल तक गिरने की उम्मीद है।

निवेशकों की दिलचस्पी होने भर से नहीं बनेगी बात

अमिता बत्रा

भारत में निवेश से जुड़ी संभावनाएं तो अपार हैं परंतु प्रतिस्पर्धा भी तीक्ष्ण है और इसे ध्यान में रखते हुए उसे अपनी व्यापार नीति उदार बनाने की आवश्यकता है। इस महीने के शुरू में ताइवान की राजधानी ताइपे में मुझे शिक्षाविदों, विचारकों और कारोबारी समूहों के साथ चीन पर चर्चा करने करने का अवसर प्राप्त हुआ था। इसके अलावा वैश्विक मूल्य व्यवस्था (जीवीसी) में विविधता से संबंधित रणनीति और निवेश के एक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में भारत की क्षमता, विशेषकर सेमीकंडक्टर एवं चिप विनिर्माण क्षेत्र पर भी व्यापक चर्चा हुई।

इन चर्चाओं के बाद मेरे मन में तनिक ही संदेह रह गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नजरिया सकारात्मक रहा है। इसका कारण आर्थिक वृद्धि के स्तर पर न केवल भारत का मजबूत प्रदर्शन रहा है बल्कि, कदाचित इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण कारण वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर उथल-पुथल है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अमेरिका और चीन के बीच व्यापार एवं तकनीक में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है और तनाव भी उफान पर है। इसके अलावा यूक्रेन संकट के बाद भू-राजनीतिक बिखराव, जीवीसी विविधता रणनीति में मित्र देशों के बीच बढ़ता सहयोग और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का सामरिक महत्त्व आदि भी महत्त्वपूर्ण कारण रहे हैं।

ताइवान की कंपनियों के लिए चीन में कारोबारों पर बढ़ता नियामकीय शिकंजा और सत्ताधारी दल का मजबूत नियंत्रण कारोबार की दूसरी जगह तलाशना एक अतिरिक्त कारण हो गया है। इसके साथ ही पिछले कुछ वर्षों में भारत के साथ बढ़ता द्विपक्षीय सहयोग भी ताइवान की कंपनियों को

आकर्षित कर रहा है।

मगर ये कारक भारत के पक्ष में निर्णायक बढ़त देने की क्षमता नहीं रखते हैं। एक दशक से अधिक समय तक वियतनाम उन कंपनियों के लिए पहली पसंद रहा है, जो चीन से बाहर अपना विनिर्माण कारोबार ले जाना चाह रही हैं। इसके लिए कंपनियों ने कई कारक एवं इनसे होने वाले लाभों का उल्लेख किया है।

मसलन, दक्षिण-पूर्व एशिया संघ (आसियान) के सदस्य देश के रूप में यह यूरोपीय संघ (ईयू), क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और कॉम्प्रिहेंसिव ऐंड प्रोग्रेसिव ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में शामिल रहा है। इसके साथ ही भूमि एवं श्रम बाजार और विदेशी निवेश जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में वियतनाम में निरंतर सुधार होते रहे हैं।

जहां तक भारत की बात है, एफटीए के मोर्चे पर हाल में प्रगति जरूर हुई है मगर आरसेप में बातचीत के अंतिम चरण में पहुंच कर कदम पीछे खींचने से क्षेत्रीय निवेशकों को निराशा हुई है। यह भी स्पष्ट है कि ताइवान के निर्यातोन्मुखी निवेशकों के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का एफटीए ईयू के साथ चल रही एफटीए पर बातचीत की तुलना में अधिक मायने नहीं रखता है। यह पहलू काफी महत्त्व रखता है क्योंकि पारिश्रमिक सहित तेजी से बढ़ती उत्पादन लागत, आधारभूत ढांचे में संभावित कमजोरी और उपलब्ध भूमि की कमी इस धारणा को बल दे रहे हैं कि वियतनाम विदेशी निवेश आकर्षित करने और आपूर्ति तंत्र स्थानांतरित करने के मामले में ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है जहां से और अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ईयू के साथ एफटीए पर वार्ता जल्द पूरी हो जाती है तो इससे भारत निवेश करने के लिहाज से तुलनात्मक रूप से अधिक आकर्षक हो जाएगा। वियतनाम के अलावा दक्षिण-पूर्व एशिया की दूसरी एकीकृत अर्थव्यवस्थाओं के साथ भी भारत की तुलना की जा रही है। उदाहरण के लिए थाईलैंड और मलेशिया ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए चीन का असरदार विकल्प समझे जाते हैं। पैकेजिंग कंपनियां थाईलैंड का रुख कर रही हैं, वहीं असेंबली इकाइयां मलेशिया जा रही हैं। मलेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया के उन देशों में शामिल रहा है, जो वैश्विक एवं क्षेत्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के साथ सबसे पहले जुड़े हैं।

आपके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध : बृजमोहन

रायपुर। रायपुर दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने आज ब्राह्मण पारा और कंकाली पारा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान क्षेत्र की जनता का अपने विधायक बृजमोहन अग्रवाल के प्रति अपार स्नेह देखने को मिला। कई घरों में बहनों ने आरती की थाल सजाकर अपने विधायक भाई बृजमोहन अग्रवाल का स्वागत किया तो कई बहनों ने मुंह मीठा करा कर उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी। बृजमोहन ने भी वरिष्ठजनों का चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लिया।

गौरतलब है कि बृजमोहन अग्रवाल का ब्राह्मण पारा क्षेत्र से काफी जुड़ाव रहा है। छात्र राजनीति के दौर से उनके ज्यादातर मित्र यहीं से आया करते है। यही वजह है कि बृजमोहन को यहां परिवार सा विशेष प्रेम और स्नेह घर-घर मिलता है।

आज अपने जनसंपर्क के दौरान छोटी-छोटी सभाओं में जन समूह को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर शहर के विकास में मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य किया है। हर घर तक विकास की किरण पहुंचे लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिले इसके लिए अनेक कार्य क्षेत्र में कराए हैं।

परंतु विकास कभी पूर्ण नहीं होता यह एक सतत प्रक्रिया। आने वाले कल में भी यह बृजमोहन आपके क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

बृजमोहन ने कहा कि पिछले 5 वर्षों से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार ने गांव गरीब और किसानों को तो ठगा ही है शहरी क्षेत्र में भी इन्होंने लूट मचाई है। सरकारी योजनाओं के नाम पर हजारों करोड़ों का घोटाला यह कांग्रेस की सरकार कर चुकी है। हम अपने रायपुर शहर की बात करें तो घर से बाहर सड़क पर निकलते ही कांग्रेस सरकार की करतूत साफ तौर पर दिखाई देती है। कांग्रेस शासित नगर निगम के गड्ढों में लोग रोजाना गिर रहे हैं, सड़क पर उड़ती दूर के चलते लोग बीमार हो रहे हैं। परंतु लापरवाह निगम प्रशासन मौन है। सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसियों को जनता की तकलीफ दिखाई नहीं देती। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि कांग्रेस की सरकार को जनता उखाड़ फेंके और प्रदेश में पुनः विकास की गंगा बहाने के लिए कमल फूल में अपना वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं।

इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल के साथ सुभाष तिवारी,मृत्युंजय दुबे, योगेश तिवारी,सरिता दुबे सहित सैकड़ों को संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पीएम मोदी की गारंटी पर है, जनता को विश्वासः राजेश मूणत

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेश मूणत का चुनावी अभियान जारी है। वह लगातार अपनी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने मंगलवार सुबह 9 से लेकर देर शाम तक विभीन इलाकों में करीब 15 स्थानों पर जनता के बीच जाकर छोटी- छोटी जनसभाएं की। श्री राजेश मूणत ने बताया कि वह जहां जा रहे हैं,वहां आम जनता कांग्रेस सरकार की शिकायतें लेकर पहले से तैयार खड़ी रहती है। मूणत ने विश्वास प्रकट किया कि कांग्रेस के प्रति जनता की नाराज़गी और भाजपा को मिल रहा जनसमर्थन इशारा कर रहा है कि रायपुर पश्चिम विधानसभा समेत संपूर्ण छत्तीसगढ़ में फिर कमल खिलने वाला है।

श्री राजेश मूणत ने बताया कि भाजपा के चुनाव प्रचार के अभियान हमारा प्रयास है कि हम अपने कार्यकाल की उपलब्धियों के जनता के बीच लेकर जाएं,लेकिन जनता के भीतर कांग्रेस की वादा खिलाफी को लेकर जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। अपने चुनाव प्रचार के दौरान श्री राजेश मूणत ने जनता से कहते दिखे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रैलियों में फिर जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। आम जनता को कांग्रेस के झूठ से सतर्क रहने की जरूरत हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग जब वोट मांगने आएं,तो उनसे पूर्व में किये गए वादों का हिसाब माँगिएगा। मूणत ने कहा कि काठ ही हांड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता ने 2018 के चुनाव में बोले गए कांग्रेस के झूठ को पकड़ लिया है। अब जनता कांग्रेस के बहकावे नहीं आने वाली है। श्री राजेश मूणत के जनसंपर्क अभियान के दौरान महिलाओं की तरफ से भाजपा के पक्ष में एकतरफा समर्थन देखा जा रहा है। मूणत के साथ भाजपा के प्रचार में लगे कार्यकर्ताओं ने बताया कि महिलाएं रायपुर पश्चिम विधानसभा में बढ़ी आपराधिक गतिविधियों और कांग्रेस के द्वारा शराबबंदी को लेकर किये गए झूठे वादे से बेहद नाराज़ हैं।आम जनता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। इसलिए वह भाजपा की हर गारंटी पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं। श्री राजेश मूणत का कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, भारतीय जनता पार्टी की छवि जनता के दिलों तक कायम है। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता 5 साल पहले भाजपा के शासनकाल में हुए विकासकार्यों को याद कर रही हैं। हमे पूरा विश्वास है कि मतदान की तारीख को क्षेत्र की जनता कमल पर मुहर लगाकर छत्तीसगढ़ में फिर से भाजपा की सरकार लाएगी।

पॉवर कंपनी से सीई रामकृष्ण अरविंद की भावभीनी विदाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (वाणिज्यिक एवं नियामक मामले) श्री आर.अरविंद को कंपनी मुख्यालय विद्युत सेवाभवन में भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम में पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के एमडी श्री मनोज खरे, पॉवर जनरेशन कंपनी के एमडी श्री एस.के.कटियार ने उन्हें प्रमाण पत्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। प्रबंध निदेशकगणों ने सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री आर.अरविंद की सेवाओं को प्रदेश के विद्युत विकास के लिए महत्वपूर्ण निरूपित करते हुए उनके द्वारा विद्युत मंडल एवं पॉवर कंपनी में किये गये योगदान की सराहना की तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता श्री अरविंद ने अपने कार्य अनुभव बताते हुए अपनी सफलता का श्रेय टीमवर्क को दिया तथा सेवायात्रा के दौरान अधिकारी-कर्मचारियों से मिले सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशकगण सर्वश्री एमएस कंवर, सीएल नेताम, एमआर बागड़े एवं संदीप मोदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक (जनसंपर्क) श्री गोविन्द पटेल ने किया।

दक्षिण विस सीट पर भरे गए सर्वाधिक नामांकन

रायपुर। सूबे की राजधानी रायपुर में विधानसभा निर्वाचन-2023 के अंतर्गत अंतिम दिन सातों विधानसभा में 49 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। धरसींवा विधानसभा क्रमांक-47 में 17, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक-48 में 25, रायपुर पश्चिम विधानसभा-49 में 28, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक-50 में 19, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 में 32, आरंग विधानसभा क्रमांक-52 में 16, अभनपुर विधानसभा क्रमांक-53 में 19 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए गए। इस प्रकार अब तक कुल 250 नामांकन दाखिल कर दिए गए हैं। सोमवार को कुल 32 नाम निर्देशन पत्र लिए गए। इनमे धरसींवा विधानसभा क्रमांक-47 के लिए 2 ,रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्रमांक-48 के लिए 4, रायपुर पश्चिम विधानसभा-49 के लिए 3, रायपुर उत्तर विधानसभा क्रमांक-50 के लिए 3, रायपुर दक्षिण विधानसभा क्रमांक-51 के लिए 8, आरंग विधानसभा क्रमांक-52 के लिए 3 और अभनपुर विधानसभा क्रमांक-53 के 9 नाम निर्देशन पत्र शामिल हैं।

भाजपा ने लांच किया अपना चुनावी एंथम

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना चुनावी एंथम लॉन्च किया है। बीजेपी ने इसे छत्तीसगढ़ी, हल्बी, गोंडी 3 भाषाओं में बनाया है। लांचिंग के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर आक्रोश हैं, विकास कार्य शून्य हो गए हैं, जब हमारी सरकार थी सरगुजा में अनुसूचित जनजाति के नौजवानों को प्रथमिकता देकर शिक्षा देते थे, कांग्रेस के आने के बाद वो भी बंद हो गयी।उन्होंने कहा कि हमारे समय में नक्सलवाद सिकुड़ रहा था जो एक बार फिर बीच में आ गया है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के नाम से बदनाम हो चुका हैं। 20 लाख से ज्यादा युवा निराशा में डूब गए है। युवाओं को लगता है हमारा भविष्य कांग्रेस के राज में सुरक्षित नही हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हैं, लोग चुनाव का इंतेज़ार कर रहे हैं। जो रायपुर क्षक्षक के 15 सालों में महानगर का स्वरूप ले रहा था, लोग आते थे तो कहते हैं रायपुर बदल चुका है। आज रायपुर गड्ढापुर, चाकुपुर हो गया हैं, 2003 में एक वातावरण बना था, कांग्रेस सरकार के खिलाफ आज वैसा ही वातावरण निर्मित हो गया है।

चारों ओर चर्चा का विषय बनी भाजपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा की चुनावी तैयारी

रायपुर। चुनाव...चुनाव और चुनाव। इस रंग में राजधानी रायपुर अब पूरी तरह रंग गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और मैदान में खड़े निर्दलीय उम्मीदवारों को कड़ी टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा की चुनावी तैयारी चारों तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है।

रायपुर उत्तर विधानसभा सीट (क्रमांक-50) से बीजेपी प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा के जनसंपर्क का क्रम दिन-ब-दिन जोर पकड़ रहा है। उत्तर विधानसभा क्षेत्र की हर गली और मुहल्ले तक श्री मिश्रा पहुंच रहे हैं। लोगों से रु-ब-रु मुलाकात कर रहे हैं। दौरा और जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ श्री मिश्रा ने शंकरनगर वार्ड क्रमांक- 30 का दौरा किया। इस दौरान भाजपा मंडल शंकरनगर के अध्यक्ष अनूप खेलकर प्रमुख रूप से उनके साथ थे। सुबह लगभग 7.30 बजे उन्होंने पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और विजयी होने का आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात उन्होंने शंकर नगर वार्ड के विभिन्न मुहल्लों का सघन दौरा कर जनसंपर्क किया।

वे शंकर नगर वार्ड के चौपाटी से कावड़ियाजी लाइन, अन्नपूर्णा डेयरी से जया मेडिकल, जनता किराया भंडार होकर पोस्ट ऑफिस, दास ज्वेलर्स से दत्ता गार्डन होते हुए दुर्गा ग्राउंड, मनचंदा लाइन से गोरखा कॉलोनी, मूनलाइट स्कूल से रामदास फर्सी मोहल्ला, नत्थानी अपार्टमेंट से वैष्णव देवी मंदिर, नेताजी चौक से गीत भवन होकर स्टेट बैंक क्षेत्र, आशियाना अपार्टमेंट से बजरंग मंदिर से दिलीप नामपल्लीवार गली, राजपूत मोहल्ला से ईश्वरी नगर, गग्गी लाइन होकर मंडल बाड़ा से बाल उद्यान से जनता गुजर लाइन से चोपड़ा कॉम्प्लेक्स से हुए होते हुए वीरेन्द्र पांडेय गली, डॉ. अशोक त्रिपाठी के निवास से संजय श्रीवास्तव के निवास होते हुए जगदीश होटल तक सघन जनसम्पर्क किया और शहरवासियों से भाजपा बहुमत से विजयी बनाने की अपील की।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

जनकल्याणकारी नीतियों से भयभीत भाजपा : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि भूपेश सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों से भयभीत भाजपा ने पहले भूपेश सरकार की योजनाओं का विरोध किया, भ्रम फैलाने का प्रयास किया, मोदी सरकार के माध्यम से अड़चन डालने का प्रयास किया और अब भाजपा कांग्रेस द्वारा की जा रही घोषणाओं का भी विरोध कर रही है और भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ के 9 भाजपा सांसद पूरे पांच

साल मोदी सरकार के साथ मिलकर हर पल यह षड्यंत्र रचते रहे किस प्रकार से भूपेश सरकार की योजनाओं को रोका जाए। जब भूपेश सरकार ने किसानों को 2500 रु. समर्थन मूल्य देने की बात कही तब मोदी सरकार ने सेंट्रल पूल में चावल लेने से मना कर दिया, धान खरीदी के समय केंद्र सरकार बारदाने की आपूर्ति रोक देती है, कभी मोदी सरकार कहती है कि हम केंद्रीय पूल में उसना चावल नहीं लेंगे। जैसे ही भूपेश सरकार ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की घोषणा की भयभीत मोदी सरकार और भाजपा ने छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी के कोटे को 86 लाख मिट्रिक टन से घटाकर 61 लाख मिट्रिक टन कर दिया। कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 76 प्रतिशत प्रतिशत आरक्षण के विधेयक को अमित शाह के दबाव में राज भवन में ही रोक दिया गया। भूपेश सरकार ने जब पुरानी पेंशन स्कीम की घोषणा की तो मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के कर्मचारीयों द्वारा जमा किया गया।

भूपेश सरकार आदिवासी समुदाय का सम्मान कियाः ठाकुर

रायपुर। रायपुर भाजपा के द्वारा छत्तीसगढ़ की बोली भाषा में थीम जारी करने पर तंज करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ी बोली भाषा खान-पान, रहन-सहन, तीज त्यौहार, परंपरा संस्कृति को उभारने का काम किया, देश में नई पहचान दिलाने का काम किया तब भाजपा को छत्तीसगढ़ की बोली भाषा की याद आ रही है। 15 साल जब सत्ता में भाजपा थी तब छत्तीसगढ़ी बोली

भाषा के लिए कुछ नहीं किया गया। भाजपा के नेता छत्तीसगढ़ी बोलने वालों को कमतर आते थे और हीन भावना से देखते थे। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि पंद्रह साल छत्तीसगढ़ को चारागाह समझने वाली भाजपा अगर छत्तीसगढ़ को महतारी कह रही है तो वह भी भूपेश बघेल की देन है। भूपेश सरकार द्वारा विश्व आदिवासी दिवस के दिन को अवकाश घोषित किया और आदिवासी समुदाय का सम्मान किया। छत्तीसगढ़ में तीजा पोरा के लोक पर्व के दिन शासकीय अवकाश भूपेश सरकार द्वारा घोषित किया गया। भूपेश सरकार बनने के बाद तीजा पर्व को बड़े ही गौरव के साथ मुख्यमंत्री निवास में मनाया जाता है और उस दिन प्रदेश की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री निवास को अपना मायका समझ कर बड़े ही हर्ष से वहां इस लोक पर्व और छत्तीसगढ़ी व्यंजनो का मुख्यमंत्री के साथ आनंद लेती है। यह वही बीजेपी है जो छत्तीसगढ़िया वाद के खिलाफ है बोरे बासी दिवस का विरोध करती है।

प्याज के दाम चुनाव में मुद्दा मोदी राज में महंगाई बढ़ीः शुक्ला

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण प्याज के दाम 80 रू. हो गयी है तथा राहर दाल 170 रू. किलो में बिक रहा है। आम आदमी का जीवन महंगाई के कारण कठिन हो गया है। इस चुनाव में महंगाई जनता का मुद्दा है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, 100

दिन में महंगाई कम करने का वायदा करने वाले मोदी के राज में आजादी के बाद सबसे ज्यादा महंगाई है। महंगी गैस, महंगा तेल, थोक और खुदरा महंगाई आजादी के बाद सर्वोच्च शिखर पर है, सिर्फ सत्ता की भूख में मोदी सरकार आम जनता की कमर तोड़ रही है, फिर भी महंगाई से देशवासियों को लूटने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रही है। पेट्रोल-डीजल 100 के पार, रसोई गैस 1000, खाने का तेल 200 के पार। आम जनता बेबस और लाचार है पर मोदी सरकार केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों के मुनाफे की सोच रही है। मोदी सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी विगत 7 साल में 258 परसेंट बढ़ाया है और डीजल पर 820 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इन तमाम आंकड़ों के बावजूद मोदी सरकार द्वारा महंगाई को झूठलाया जाना यह प्रदर्शित करता है कि महंगाई को काबू करना मोदी सरकार के बस में नहीं है।

वादाखिलाफी भाजपा का चरित्र : वर्मा

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। आम जनता के आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि के कीर्तिमान स्थापित किये है। सत्ता में रहने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता किसान विरोधी षड्यंत्र रचते रहे, और चुनाव आते ही किसान हितैषी होने का स्वांग रचते हैं। रमन सिंह ने 15 साल किसानों को

बोनस के नाम पर ठगा, चुनावी साल को छोड़कर कभी किसानों को बोनस नही दिया। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का वादा था, किए ठीक उल्टा, कृषि की लागत मोदी निर्मित महंगाई के चलते तीन गुना बढ़ गई है। 700 रू. प्रति बोरा का पोटास सीधे 1500 रू. कर दिया गया, खाद सब्सिडी में पिछले बजट में ही सीधे 35 हजार करोड़ की कटौती मोदी सरकार ने की है।3 कृषि के तीन काले कानूनों के खिलाफ़ हुए किसान आंदोलन के समय 700 से अधिक अन्नदाताओं की मौत के बाद देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि एमएसपी के कानूनी गारंटी के वादे पर भी अब तक प्रधानमंत्री मौन हैं। सरकार में रहते खेतों की सिंचाई के लिए बनाए बांधों पर कब्ज़ा करने वाले, किसानों की जमीनें हड़पने वाले भाजपाई किस मुंह से किसान हितैस होने का ढोंग कर रहे हैं? रमन राज में कमीशनखोरी के चलते कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए काउंटर तय हुआ करते थे, भूपेश सरकार में सब्सिडी की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा हो रहे है।

कांग्रेस ने ओपी चौधरी की निर्वाचन आयुक्त से शिकायत

रायपुर। रायगढ़ के भाजपा के प्रत्याशी ओपी चौधरी के द्वारा अपने चुनावी प्रसार-प्रचार के दौरान मंचस्थ होकर अपने निर्वाचन की संभावनाओं को अग्रसर करने के लिये और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के आशय से जानबूझकर धार्मिक प्रतीकों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने वाली वेशभूषा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया जा रहा है, ओपी चौधरी द्वारा उक्त वेशभूषा के फोटो अपने फेसबुक पेज पर भी शेयर की गयी है। इसके खिलाफ कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से शिकायत करते हुये कहा कि ओपी चौधरी द्वारा यह कृत्य स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा प्रत्याशियों के द्वारा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति और राजनैतिक हितो को साधने के लिये अबोध एवं नाबालिग बच्चों एवं धार्मिक प्रतीको वाली वेशभूषा का राजनैतिक उपयोग करना घोर आपत्तिजनक और निंदनीय है। और यह छत्तीसगढ़ के इस बार के विधानसभा चुनाव में पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पूर्व भी साजा से भाजपा प्रत्याशी ईश्वर साहू के द्वारा अपने फेसबुक आईडी से प्रसारित वीडियों में अबोध एवं नाबालिग बच्चों को उपयोग करते हुये समाज में विद्वेष एवं नफरत फैलाने वाली बातें बच्चों के मुंह से बुलवाकर छत्तीसगढ़ की शांत धरा को अशांत करने का दुष्प्रयास किया गया था।

बीजेपी महंगाई बढ़ाती है, हम कम करते हैं : सीएम भूपेश बघेल

रायपुर। हमारी सरकार के पांच साल पूरे हो गए हैं, हम आपसे समर्थन लेने के लिए आपके बीच आए हैं, इस वक्त बहुत से लोग वोट काटने के लिए घूम रहे हैं उसने सावधान रहने की जरूरत है, भाजपा के लोग भ्रम फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। यह बात मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर के मूली में हुई जनसभा में कही।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बीजेपी महंगाई बढ़ाने का काम करती है, हम कम करने का काम करते हैं इसीलिए हमने 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ और सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की छूट देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के लोग भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी घोषणा नहीं पाए हैं। गृहमंत्री अमित शाह राजनंदगांव आए थे, वहां उन्होंने घोषणा की कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा सबसे बड़े भ्रष्टाचारी रमन सिंह उनके बगल में ही खड़े थे। रमन सिंह को ही उल्टा लटकाकर वह इसकी शुरुआत क्यों नहीं कर देते। रमन सिंह ने चिटफंड कंपनी के पैसे खाए, नान घोटाला, चावल घोटाला किया। यहां तक कि टिफिन, चप्पल, मोबाइल वितरण तक में घोटाला किया। रमन सिंह ने युवा, आदिवासी, किसान सबको ठगा। 21 सौ रुपये में धान खरीदी, किसानों को बोनस देने और आदिवासियों को जर्सी गाय देने का वादा कर मुकर गए। सबके राशन कार्ड कटवा दिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी छत्तीसगढ़ के खदान, नगरनार स्टील प्लांट सब बेचने का काम कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि राहुल गांधी जी ने किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था। हमने दो घंटे के भीतर 19 लाख किसानों का साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया। 25 सौ रुपये में धान खरीदने का वादा पूरा किया। मोदी जी को यह सब पसंद नहीं आया। मोदी ने कहा कि धान पर आप बोनस देते हैं, हम आपसे चावल खरीदना बंद कर देंगे। हमने राजीव गांधी किसान योजना लाकर किसानों को धान का सबसे अधिक दाम दिया। कोरोना काल में भी तेंदूपत्ता, महुआ, इमली की खरीद बंद नहीं की। हम संकट में भी आपके साथ खड़े रहे। तीन महीने का राशन एडवांस में जरूरतमंदों को पहुंचाया। उसी समय किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त पहुंची। 26 लाख परिवारों को मनरेगा से काम दिया।

निगरानी दलों ने अब तक जब्त 38 करोड़ 34 लाख से अधिक का शराब- सामान

रायपुर। राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद से 29 अक्टूबर तक की स्थिति में 38 करोड़ 34 लाख रुपए से अधिक की अवैध धन राशि तथा वस्तुएं जब्त की गई हैं। इनमें दस करोड़ 11 लाख रुपए की नगद राशि भी शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों (इन्फोर्समेंट एजेंसीज) द्वारा निगरानी के दौरान विगत 29 अक्टूबर तक 30 हजार 840 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है,

जिसकी कीमत 90 लाख 87 हजार 532 रुपए है। सघन जाँच अभियान के दौरान 14 करोड़ 82 लाख 76 हजार रुपए कीमत के 184 किलोग्राम से अधिक कीमती आभूषण तथा रत्न भी जब्त किए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सामग्रियां जिनकी कीमत नौ करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक है, भी जब्त की गई हैं।मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के परिपालन में राज्य में विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत निगरानी दलों द्वारा सघन जाँच की कार्यवाही लगातार जारी है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.